The question was put and the motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.

SHRI SALMAN KHURSHEED : Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now, the House stands adjourned for lunch to meet at 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at
thirty-eight minutes past one of the clock

The House re-assembled after lunch at
thirty-five minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN) in the Chair.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN) : Now, we will take up the Private Members' Business (Resolutions). Resolution No. 1, Shri Prakash Javadekar.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे कुछ कहना है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ आपसे यह अर्ज करना चाहती हूँ कि आज तेलंगाना के ऊपर इतना महत्वपूर्ण Private Member's Resolution है और सत्ता पक्ष के केवल एक सदस्य हैं, even Parliamentary Affairs Minister तक यहाँ पर नहीं हैं। जो दोनों मंत्री बैठे हैं, वे भी लोग सभा के सम्माननीय सांसद हैं। रूलिंग पार्टी से यहाँ कोई भी सदस्य नहीं है, मैं चेयर से अपनी यह पीड़ा व्यक्त कर रही हूँ। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : मिनिस्टर हैं।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, देख लीजिए, कितने आदमी हैं, सिर्फ तीन आदमी हैं। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN) : That is not the business of the Chair. It is not my business. Najmaji, that is not the business of the Chair. ...(*Interruptions*)...

DR. NAJMA A. HEPTULLA (Madhya Pradesh) : Are you going to take care, Mr. Mukul Wasnik?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR (Maharashtra) : Sir, I move the following Resolution:-

[SHRI PRAKASH JAVADEKAR]

"Having regard to the fact that-

(i) the State of Andhra Pradesh was formed in the year 1956 after amalgamating Telugu speaking areas, but the first State Reorganisation Commission had recognized Telengana as a potential separate state and the first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru had even assured justice to Telengana while inaugurating the new state;

(ii) despite all these assurances, due to the lop-sided policies of the governments in the State, some areas have remained neglected in the fields of education, employment, irrigation, development, etc., and this neglect and backwardness have led to an acute feeling of alienation among the people of Telengana region, who have been demanding a separate state since 1969;

(iii) Telangana consists of ten districts of Andhra Pradesh, namely - Hyderabad, Rangareddy, Mahboobnagar, Medak, Nalgongda, Khammam, Warrangel, Karimnagar, Adilabad and Nizamabad and nine out of these ten districts are recognized by the Government of India as backward, despite availability of many natural resources, the benefits have failed to reach its people;

(iv) the experience of creation of smaller states has been good as it makes administration smoother and efficient coupled with higher development of the areas that have been neglected and from the people's perspective, this gives them more easy access to the government and reduces disparity level between the developed and non-developed areas;

(v) there is merit in the demand for a separate state of Telengana as it serves the cause of geographical continuity, economic viability as well as administrative convenience; and

(vi) the Central Government had announced on 9th December, 2009 that the process of formation of separate State of Telengana has begun but now the Government is backtracking and has taken a complete U-turn on this promise, which has resulted in continuous agitation in the region; this House urges upon the Government to create a separate State of Telengana with a separate Legislature, Executive and Judiciary in accordance with the Constitution of India."

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि विपक्ष के लोगों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज करके कांग्रेस के इस प्रयास को भी पराजित किया है। तेलंगाना के प्रति यही कांग्रेस की नीति है कि वह तेलंगाना के साथ हमेशा बिट्रेयल करती आ रही है। जब आज यहाँ उसका एक भी मेम्बर नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है? **...(व्यवधान)...** एक है, लेकिन एक ही है और वे भी हमारे दोस्त हैं। यह अच्छी स्थिति नहीं है।

सर, तेलंगाना के हमारों गाँवों में 4.5 करोड़ लोग और पूरी दुनिया में लाखों NRIs, जो तेलंगाना के हैं, और हर गाँव, गली-कूचे में लोग आज यह चर्चा देख रहे हैं, क्योंकि उनकी लोकतंत्र में आस्था है। वे समझते हैं कि राज्य सभा और लोक सभा लोकतंत्र का मंदिर हैं, जिस मंदिर में न्याय की गुहार लगाने पर न्याय मिलेगा। इसलिए लोकतंत्र की हर परीक्षा में तेलंगाना की जनता खरी उतरी है। चाहे चुनाव हो, आन्दोलन हो, त्याग हो, आप कोई भी कसौटी रखेंगे, तो तेलंगाना के लोगों ने हमेशा अपने cause का साथ दिया है और कभी भी उससे गद्दारी नहीं की है। आन्दोलन सौ फीसदी होता है, चाहे जो भी आन्दोलन हो। 70 के दशक में 1968 से एक बहुत बड़ा आन्दोलन शुरू हुआ। इस आन्दोलन में 700 से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या की अपना protest दर्ज कराने के लिए कि हम न्याय माँग कर रहे हैं। वे क्या माँग रहे हैं? यह कोई अलगाववाद की माँग नहीं है, जो कहीं-कहीं हमें देखने को मिलती है। तेलंगाना चाहता है कि जैसा वह था और जो उसका न्याय है, वह तेलंगाना स्थापित हो, क्योंकि हम believe करते हैं कि अगर हम आज भी दो राज्य बनाएँगे, तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश, तो both the States will co-exist peacefully and prosper rapidly. यह होने वाला है। इसलिए आज इस चर्चा को सब लोग देख रहे हैं। यह आज की माँग नहीं है, इसका लम्बा इतिहास है।

सर, जो first State Reorganization Commission (SRC) बैठा था, अगर उसने किसी एक राज्य की मांग को जायज़ ठहराया है, तो वह तेलंगाना है। The first Commission was against the division of Hyderabad State and merger of Telangana with Andhra, क्योंकि उस समय आन्ध्र प्रदेश Madras Presidency का पार्ट था। एसआरसी की रिपोर्ट के पैरा 386 में लिखा है, "It will be in the interest of Andhra as well as Telangana if, for the present, Telangana area is constituted into a separate State which may be known as...", यह उन्होंने अपनी सिफारिश में लिखा है।

फर्स्ट एसआरसी ने तेलंगाना का समर्थन किया। कांग्रेस के जो लोग सैकेंड एसआरसी की बात करते हैं,वह बेमानी है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सैकेंड एसआरसी की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एसआरसी ने ही उसे जायज़ ठहराया है। फर्स्ट एसआरसी के पैरा नम्बर 388 में लिखा है, "If, however, our hopes for the development of environment and conditions congenial to the unification of the areas do not materialize..." जब कांग्रेस ने तय किया कि फर्स्ट एसआरसी की मंशा कुछ भी हो, हम मर्ज करेंगे, तो उस पर वह एसआरसी लिखता है, "That areas do not materialize and if public sentiment in Telangana crystallizes itself against the unification of the two States, Telangana will have to continue as a separate unit." पृथक तेलंगाना का आन्दोलन आज का नहीं है, मैं पचास साल पहले की बात कर रहा हूं। यह लम्बा इतिहास है, लम्बा आन्दोलन है। उसके बाद कितने नमूने लाए गए, कितने प्रॉमिस किए गए।

Sir, there was one Gentlemen's Agreement. In 1956 a Gentlemen's Agreement of Andhra Pradesh refers to an Agreement that was signed between Telangana and Andhra leaders preventing discrimination against Telangana by the Government of Andhra. Based on the safeguards only Telangana was merged with Andhra. However, none of these safeguards were implemented.

सर, जिसको Gentlemen's Agreement कहते हैं, अगर उसका gentlemanliness ही खत्म होता है, उसका प्रॉमिस ही पूरा नहीं होता है, तो क्या भरोसा किया जाएगा? उसमें एक रीजनल कमेटी की बात थी, development of economic planning within the framework of the general

[SHRI PRAKASH JAVADEKAR]

development था, unit as far as the recruitment to subordinate services, domicile का रूल था, twelve years stay in Telangana की बात थी। फिर balance of income should be reserved for expanditure on development of Telangana area था, यानी उसको आर्थिक न्याय मिलना था और Telangana should be secured to the students of Telangana and further improved था।

जो टेक्निकल शिक्षा की सुविधाएं हैं, उसमें था कि 40% सभी तेलंगाना के मंत्री होने चाहिए। यह सब कुछ उसमें लिखा था, लेकिन इन्होंने उसकी एक बात भी पूरी नहीं की। यह इतने लम्बे सालों का इतिहास है। उसके बाद मुल्की रूल्स आए। मैं लम्बा इतिहास तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरह से ये मील के पत्थर हैं। 1969 में एक Six Point Formula आया, क्योंकि 1968 में चेन्ना रेड्डी जी के नेतृत्व में एक बहुत जबरदस्त आन्दोलन हुआ था। वह लगातार 1970 तक, ढाई साल चला, जिसमें 300 से ज्यादा लोग शहीद हुए। चुनाव में उन्होंने वहां कांग्रेस से अलग होकर एक दल की स्थापना की और उसके ग्याहर सदस्य चुन कर आए। So, continuously Telangana has voted for Telangana. Telangana has aspired for Telangana and Telangana has a right to exist as Telangana. इसलिए तेलंगाना में आप कहीं भी जाओ, लोग नारा लगाते हैं, "जय तेलंगाना", "जय तेलंगाना" और हम तेलंगाना लेकर ही रहेंगे।

यह जो Six Point Formula था, वह 1969 और 1972 के एजिटेशन के बाद आया। उसमें greater financial allocation की बात थी, preference to local candidates था, recruitment of local candidates should be preferred लिखा था, Tribunals should be prolonged the process of rendering justice था। फिर 1972 में President Order 371(d) के अन्दर भी निकाला गया और Telangana agitation of1969 में जब जय आन्ध्र मूवमेंट लॉंच हुआ था, तब all safeguards, including SC judgment of Mulki Rules, were nullified with 32nd Constitution Amendment of article 371(d).

सर उसके बाद एक G.O. 610 आया। उसमें भी, G.O. is not implemented even today depriving the Telangana people of their legitimate jobs. ढाई-तीन लाख लोगों की नौकरियां मिल सकती थीं, जो नहीं मिलीं।

सर, यह लड़ाई केवल इमोशनल लड़ाई नहीं है। मैं लगातार पाँच साल तेलंगाना के हर जिले और हर तहसील में घूमा हूं और मैंने देखा है कि उनकी क्या पीड़ा है। यह केवल भावना की बात नहीं है, इसमें आर्थिक मामले भी हैं, इरिगेशन के मामले भी हैं, अन्याय के मामले भी हैं। बाद में इसके कारण Girgilani Commission बनाया गया।

यह लगातार चलता रहा, लेकिन इन सारे प्रयासों के बाद भी यह नहीं हुआ। तेलंगाना क्यों नहीं बन रहा है? तेलंगाना की जनता यह चाहती है, तेलंगाना feasible है और तेलंगाना सम्भव है। हमने तीन राज्यों का निर्माण करके दिखाया, आपको भी एक राज्य का निर्माण करना है, आपने 2004 में जो प्रॉमिस किया था। यू.पी.ए. के सी.एम. में, Common Minimum Programme में, तेलंगाना का राज्य देंगे, आपने यह वचन दिया है और यह वचन देकर इसे तोड़ा है, यही आपका इतिहास है। **...(व्यवधान)...** 2009 में भी यही किया, यह मैं आपको बता रहा हूँ। **...(व्यवधान)...**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ल) : छः साल तो नहीं किया? **...(व्यवधान)...**

श्री प्रकाश जावेडकर : मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपको सब बताउँगा। **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल : जब खुदा सत्ता में थे, तब नहीं किया। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रकाश जावेडकर : मैं आपको बता रहा हूँ। **...(व्यवधान)...** मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक मिनट रुकिए। **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल : तब चन्द्रबाबू नायडू ने आपको मना किया था। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रकाश जावेडकर : आप चिन्ता मत करिए। **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल : जब चन्द्रबाबू नायडू मना करते थे, तब नहीं किया। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रकाश जावेडकर : आप चिन्ता मत करिए। **...(व्यवधान)...** आपको भाषण का मौका मिलेगा। **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल : आपको बोलने का अधिकार नहीं है। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रकाश जावेडकर : सर, अभी आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** आप बैठिए। आप क्यों इतनी चिन्ता करते हैं? **...(व्यवधान)...**

SHRI BALBIR PUNJ (Odisha) : Sir, of all the people, the Parliamentary Affairs Minister should not be disturbing the Member who is speaking. ...(*Interruptions*)... At least, the Parliamentary Affairs Minister should not be disturbing a Member. ...(*Interruptions*)...

श्री राजीव शुक्ल : मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। **...(व्यवधान)...** Parliamentary Affairs Minister कोई टेप थोड़े ही लगाता है। इसका भी मुँह खुला होता है न? **...(व्यवधान)...**

श्री प्रकाश जावेडकर : जब आपका समय आएगा, तब आप बोलिए। पार्लियामेंट का तरीका है कि किसी को अपना समय आने पर बोलना चाहिए। **...(व्यवधान)...**

श्री राजीव शुक्ल : आप कभी नहीं बोलते हैं?

श्री प्रकाश जावेडकर : हाँ, मैं ऐसे कभी नहीं बोलता हूँ। **...(व्यवधान)...** अभी मुझे बुलाया गया है, आपको नहीं।

इसलिए, यह जो पोलिटिक्स आपने की है **...(व्यवधान)...**

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला (गुजरात) : आपको यह नहीं देना है, आप इतना ही बोल दो। **...(व्यवधान)...** आप इतना ही बोल दो **...(व्यवधान)...**

श्री प्रकाश जावेडकर : सर, अब इन्होंने क्या-क्या किया? **...(व्यवधान)...** दहलाने के लिए **...(व्यवधान)...**

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला : बाद में देखो कि तेलंगाना में या आंध्र में क्या होता है? **...(व्यवधान)...** इनको डिस्टर्ब करने से क्या होता है। आप ऐसा बोल दो कि एन.डी.ए. ने नहीं दिया, इसलिए हम भी नहीं दे रहे हैं। आप यही बोल दो। **...(व्यवधान)...** आप इतना ही बोल दो। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रकाश जावेडकर : लेकिन, ऐसा नहीं है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। **...(व्यवधान)...**

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला : आप यह बोल दो। **...(व्यवधान)...** अगर हिम्मत है, तो बोल दो। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रकाश जावेडकर : एक मिनट। **...(व्यवधान)...** सर, सवाल सिर्फ इतना ही है कि आपने लगातार एक जनआन्दोलन से, जनभावना से जुड़े एक विषय पर, जो कि feasible है, एक प्रस्ताव यहाँ लाना है। हमने पहले ही कहा है कि आप वह प्रस्ताव लाओ, बिल लाओ, हम उसे समर्थन देंगे। हम आपको ब्लैंक चेक दे रहे हैं कि आप कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करके सरकार स्थापना का प्रस्ताव लाइए, हम समर्थन देंगे, लेकिन ये लाते ही नहीं हैं।

सर, इन्होंने और क्या-क्या किया? 2004 के चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम एक पृथक तेलंगाना राज्य का निर्माण करेंगे। ऐसा करने के बाद, अब यह करना तो था नहीं, यह इरादा तो था नहीं, इसलिए प्रणब मुखर्जी कमेटी बनाई। प्रणब मुखर्जी कमेटी कौन-सी है? मैंने पूछा कि भाई, यह कौन-सी कमेटी है, सरकार ने तो ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई और प्रणब मुखर्जी तो वैसे सरकार की हर कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन यह कौन-सी प्रणब मुखर्जी कमेटी है? तो प्रणब मुखर्जी कमेटी कांग्रेस ने नियुक्त की थी, वह सरकार की नहीं थी और वे हमें चिट्ठियाँ भेज रहे हैं। वे हमें चिट्ठियाँ भेजेंगे, सब को चिट्ठियाँ भेजेंगे कि आप अपनी राय दो। हमने कहा कि पहले अपनी राय बताओ। कांग्रेस अपनी राय बताएगी नहीं और हमसे पूछेगी कि हमारी क्या राय है, उसे क्या अधिकार है? इसलिए, यह एक बहाना था और एक तरह से यह बिल्कुल एक betrayal था। इसके बाद एक Rosaiah Committee बनाई गई। जैसे ही वहाँ आन्दोलन शुरू होता है—सर, 2000 से फिर यह आग भड़की है। 700 जवानों ने, महिलाओं ने और विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। इस तरह का त्याग, बलिदान और तपस्या इस आन्दोलन में हुआ है और हर कार्यक्रम में जब कोई भी कहे 'जय तेलंगाना', तो उसके लिए लाखों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। यह यहाँ की वास्तविकता है। इसके बाद इन्होंने Rosaiah Committee बनाई। 2009 के चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ इनका समझौता नहीं था, लेकिन इन्होंने फिर भी एक प्रॉमिस दिया कि हम तेलंगाना राज्य का निर्माण करेंगे। सर, मैं betrayal की कहानी क्या कहूँ। तेलंगाना का चुनाव first phase में था और आंध्र तथा रायलसीमा का चुनाव second phase में था। ये first phase होने तक 'तेलंगाना देंगे' बोल रहे थे और जैसे ही first phase समाप्त हुआ, उस समय के मुख्य मंत्री ने तुरंत अपना स्वर बदला और भाषा बदल ली। सारी बोली बदल गई और तेलंगाना का विषय ही नहीं रहा, सब उल्टा हो गया। इस तरह betrayal की यह कहानी है। इस betrayal से लोगों में गुस्सा है और उस गुस्से के कारण लोग आज उस आन्दोलन में सब जगह आ रहे हैं। सर, 9 दिसम्बर, 2009 को इसी सदन में आकर और रात को टी.वी. पर गृह मंत्री, श्री चिदम्बरम जी ने आश्वासन दिया—"Let me announce that the process of formation of the separate State of Telangana has begun." इन्होंने 'has begun' कहा, प्रॉमिस दिया, birthday gift कहा, कुछ भी कहा, लेकिन प्रत्यक्ष यह हुआ कि 9 दिसम्बर, 2009 से आज 4 मई, 2012 है। ढाई साल बीत गए, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया।

उस पर अमल नहीं किया, उसके 15 दिन के बाद यानी 23 तारीख को ही वे बदल गए और बोले कि there is no consensus. इसमें consensus की क्या बात है, यह तो बहुमत से पारित होता है। उन्होंने सभी दलों की बैठक की और बोले कि सभी दलों की राय एक जैसी नहीं है। अगर सबकी एक राय होती, तो अलग-अलग पार्टियां बनेंगी, तो अलग-अलग मत होंगे ही, लेकिन सरकार की अपनी राय क्या है? आज तक कांग्रेस ने अपनी राय नहीं बताई। तेलंगाना के लोग वेल में आएंगे, तेलंगाना के कांग्रेस सांसद वेल में आएंगे और कहेंगे कि तेलंगाना चाहिए तथा वहां आन्ध्र में, रॉयलसीमा में, कोस्टल आन्ध्र में जाकर कहेंगे कि हम तेलंगाना का पूरा विरोध करेंगे! आज तो आप बताइए कि आखिर इस पर कांग्रेस पार्टी की राय क्या है? वे इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। सर, ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दूसरे से पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, अभी तक

चार पार्टियों ने हमें राय नहीं भेजी है। आखिर आप कौन होते हैं? हम आपको अपनी राय भेजेंगे? हम जनता के बीच जाएंगे, आपका सूफड़ा साफ करेंगे और तेलंगाना का निर्माण करेंगे। हम यह लोकतंत्र के जरिए करके दिखाएंगे। यह consensus की बात खुद की राय न देने का एक बहाना है।

सर, इसमें एक बड़ा chapter श्रीकृष्ण कमीशन है। जब श्रीकृष्ण कमीशन बना था, तब हमने उसका विरोध किया था कि यह समय निकालने का एक बहाना है। यह केवल एक बहाना है और उस बहाने में क्या हुआ? उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या आई, यह खुद कमीशन को ही पता नहीं है। उन्होंने six alternatives दिए। उन्हें एक solution देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने six solutions दिए। खुद ही तीन solution को रद्द किया ओर तीन में कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा कि किसी को कुछ पता ही नहीं चले। इससे लोग बहुत नाराज हुए और पिछले साल "सकला जनुला सम्मे" हुआ, जिसके तहत लोगों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें चार करोड़ लोग सड़कों पर आए, 42 दिन आंदोलन चला, इसमें एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई, 9 लाख employees स्ट्राइक पर थे, वहां के एक-एक employee स्ट्राइक पर थे, टीचर्स-स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर थे, Four national highways पूरे ब्लॉक थे, दो दिन पूरी ट्रेन्स blocked हुईं, 54 हजार आरटीसी बसेज् बंद थीं, सिंगरेली कॉलोनी के 62 हजार वर्कर्स भी वहां स्ट्राइक पर गए, 25 हजार electricity employees स्ट्राइक पर गए, सब lawyers ने बाइकाट किया, मंदिर के पुजारियों ने भी बहिष्कार किया, गवर्नमेंट डॉक्टरों ने बाइकाट किया, पांच सौ के पांच सौ सिनेमा हॉल्स बंद रहे, सारे autos भी बंद रहे, आपने ऐसी स्ट्राइक कभी नहीं देखी होगी। It was an unprecedented public response. इस तरह से पूरा तेलंगाना बंद रहा। एक लोकतंत्र में बिना हिंसा के ऐसा जबर्दस्त आंदोलन पिछले अनेक सालों में नहीं हुआ, जिसको तेलंगाना के लोगों ने करके दिखाया, लेकिन फिर भी सरकार ने कद्र नहीं की, अपने promise पर आप खरे नहीं उतरे।

अब आज़ाद कमेटी के बारे में कहने लगे हैं। मैंने पूछा कि यह कौन-सी आज़ाद कमेटी है? कहा गया है कि यह गुलाम नबी आज़ाद कमेटी है। यह कमेटी पर कमेटी बनाने की क्या आवश्यकता है? आप प्रस्ताव लाइए, बिल लाइए, उसको पास करने की गारंटी हम देते हैं, आप और हम मिल कर पास करेंगे और तेलंगाना का निर्माण हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा न करके सिर्फ confusing statement देंगे। होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर एक भाषा बोलते हैं, गुलाम नबी आज़ाद दूसरी भाषा बोलते हैं, चिदम्बरम जी तीसरी भाषा बोलते हैं, अहमद पटेल चौथी भाषा बोलते हैं। सब अपनी-अपनी भाषा बोलते हैं। उनके General Secretary तो ऐसे विषय पर बोलते ही नहीं हैं।

सर, इसमें एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह जो श्रीकृष्ण कमीशन बना, उसका एक undisclosed chapter है। एक तो पांच chapter की रिपोर्ट लोगों को दी, लेकिन एक छठा chapter है, जो undisclosed था, वह हाई कोर्ट के सामने गया और हाई कोर्ट ने उस पर comment किया कि ऐसा कमीशन हमने कभी नहीं देखा। वह सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस का कमीशन है, लेकिन आप किस तरह से उसको यूज करते हैं, यह इससे पता चलता है। उसके दूसरे सदस्यों ने क्या किया, वह तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक supplementary note लिखा। उस supplementary note में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस को political management करना चहिए। यह कमीशन recommend कर रहा है कि political management कैसे करना चाहिए। "There is a need for ensuring unity among the leaders of the ruling party in the State". वह कहीं भी नहीं है, तो यहाँ कैसे होगी? "Action also needs to be initiated for softening the TRS, to the extent possible, especially in the context of the fact that TRS has threatened to launch a civil disobedience movement". कमीशन ने आगे लिखा है, "The Congress High Command must sensitize its own MPs and MLAs to educate them about the wisdom of arriving at an acceptable and workable

[श्री प्रकाश जावेडकर]

solution with the ruling party and the main Opposition party for Telangana demand being brought on the same page”. क्या यह किसी कमीशन की रिपोर्ट हो सकती है? उसने आगे लिखा है, “There is a need for providing placement of representatives of Telangana in key positions, such as Chief Minister, Deputy Chief Minister, but it has not been done. The ruling and the main Opposition party are being brought on the same page. The political party, TRS, must be softened. It must be ensured that MPs and MLAs of the ruling party are sensitized”.

मीडिया को कैसे कंट्रोल करें, यह भी कमीशन बता रहा है। उसने कहा, “Except for two channels, Raj News and HMTV, the rest of them are supporters of united Andhra Pradesh. A coordinated action on their part has to be the potential of shaping the perception of the common man. However, the big journalists in the respective regions are locals and are likely to capture only those events and news which reflect the regional sentiments”. क्या मीडिया के बारे में कमीशन ऐसा लिख सकता है? वह आगे लिखता है, “The print media is hugely dependent on Government for advertisement revenue, and, if carefully handled, can be effective tool to achieve this goal”. “Achieve this goal” means not forming Telangana, betraying Telangana. इस goal को achieve करने के लिए कमीशन की यह रिपोर्ट है।

अगर आंदोलन होगा, तो कौन-से हथियार का उपयोग होगा, यह भी कमीशन ने सुझाया है। कमीशन लिखता है, “In my discussion with the Chief Secretary and the DGP, the kind of equipment and weaponry to be used were also discussed, and it was agreed that weaponry to be used were also discussed, and it was agreed that weaponry used should be such as not to cause fatal injuries, while at the same time, effective enough to bring the agitationists quickly under control”. हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जतायी है कि क्या ऐसी रिपोर्ट होती है? The manual suggested by the Committee, in its secret supplementary note, possess an open challenge, if not threat, to the very system of democracy, Sir.

इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि आज तक तो आपने CBI का उपयोग Congress Bureau of Investigation के रूप में किया, अब यह CCT नया है, Congress on Talangana तो यह भी Congress Committee on Telangana होगा। अब आप चाहे कोई भी कमीशन नियुक्त करें या कोई भी कमेटी नियुक्त करें, वह Congress Committee on Telangana के रूप में काम करेगी। अगर इस तरह से काम होगा, तो यह लोगों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा होगा। इसलिए इस आंदोलन ने अपनी जनतांत्रिक भावना को रखा है। इसके लम्बे इतिहास में एक जायज माँग के लिए लोगों ने त्याग किया है कि तेलंगाना separate होना चाहिए और यह हो सकता है।

जब लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्य मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मुलायम जी थे, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और अटल जी प्रधान मंत्री थे, तो उस समय राज्यों के विभाजन पर तीनों का विरोध था। उस पर किसी का भी विरोध हो सकता था, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन विरोध होने के बावजूद अटल जी ने परिस्थिति को इस तरह से tackle किया कि तीनों मुख्य मंत्रियों ने खुद प्रस्ताव रखा और

3.00 P.M.

वह पारित हो गया। तीन राज्य बन गये और यहाँ एक दिन में वह सर्वसम्मति से हो गया। आज भी हम कहते हैं कि हम आपको open blank cheque दे रहे हैं कि आप प्रस्ताव लाइए, हम बिल पास करेंगे, तेलंगाना का निर्माण होगा और हम जय "तेलंगाना" कहेंगे। फिर तेलंगाना भी फूलेगा-फलेगा, आन्ध्र प्रदेश भी तरक्की करेगा और दोनों राज्य शांति से रहेंगे। यही हमें चाहिए और यह करने के लिए आप आज निश्चित आश्वासन दीजिए, लोग उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसीलिए हम यह विषय चर्चा में लेकर आए। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय तेलंगाना।

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO (Andhra Pradesh) : Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to speak. I am a doctor by profession. Neither I have got capacity like Prakashji nor have I got that kind of oratory. If you permit me, Sir, I will present a few of the facts here. With great respect to my friend, Prakash Javadekarji, he has conveniently forgotten one fact when he was telling many things, what the history was and how it happened and all other such things. Sir, here I may be permitted to bring to your kind notice that on 2nd April, 2002, Shri L.K. Advaniji, now the Chairperson of NDA, and the then Deputy Prime Minister, had written a letter to Mr. Narendra stating that "Regional disparities in economic development could be tackled through planning and efficient use of available resources. Therefore, the Government does not propose creation of a separate State of Telengana." Sir, I do not think there is any dispute about Shri Advani's letter of 2nd April, 2002. There was a historic BJP meeting which took place in my State in a place called Kakinada. Sir, in their plenary or whatever it is, I do not know exactly, they passed a resolution and with 'one vote, two States' slogan they went for election, Sir. The NDA formed the Government after that election. Sir, after that it was conveniently forgotten by the BJP about the separate State of Telengana. I do not know and I cannot explain the historic reason for that, Sir. They only can better explain, Sir. Coming to the present state, with high respect to the parties and the Members who are demanding a separate State of Telengana, I rise here to express my views and also bring some historical facts to the notice of this August House. There is nothing wrong with a demand for a separate State. There is no illegality or unconstitutionality for such a demand and I totally support the right to make a demand. But before taking any such decisions, either to divide or to keep a State unified, one should take historical background, realities and facts into consideration. Sir, regarding the historical background of the formation of the State of A.P., I would like to bring to your kind notice a few facts and, through you, to the notice of this August House. Out of the humiliation, insults and deprivation in several spheres to the Telugu speaking people in Hyderabad State for decades, which went on for decades during the earlier regime before the popular Government, people of different convictions, different parties, religions had craved for Vishal Andhra or United A.P. and requested the leaders from Andhra region and made eloquent and passionate demands in Parliament for the formation of United Andhra.

[DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO]

In this respect, I want to bring it to the kind notice of this House that this very August House, when the formation of the State of Andhra Pradesh was discussed in the year 1953, had discussed the formation of linguistic States. The Telegu-speaking Members, elected from the then State of Hyderabad, expressed their anguish for creating the first linguistic State of Andhra Pradesh, without them. We can go into the records, the public representatives from the State of Hyderabad—now Telangana—had, in the 1953 debates, strongly objected to it. The great son of the soil, Dr. Baba Saheb Ambedkar, and one of our greatest patriots, a communist in true spirits, Shri Putrapali Sundraya, of whom the country is proud of, had also participated in the said debate. Similarly, if we go into the 1953 debates of the Lok Sabha, we would find that all the elected Members from the Telugu-speaking part of Hyderabad, had vehemently opposed the formation of the State of Andhra Pradesh. So, it was not only objected in our House, but also in the other House. This is the history and it is on records. It is also on records what Madam Indira Gandhi, the beloved *amma* of the poor people of this country, had said in the Parliament. She spoke twice on this issue. Both the times, she had justified the combined State of Andhra Pradesh. It can also be seen on the records. The then Chief Minister of the State of Hyderabad, Shri Burgula Ramakrishna Rao, had sacrificed his position for the formation of Vishal Andhra. That is the history of the Vishal Andhra. Also, in the year 1953, the municipal corporations of Hyderabad and Secundrabad made a unanimous resolution to make the twin cities as the capital of the first linguistic State. The demand for the formation of Andhra Pradesh or Vishal Andhra was not initiated by the people of Andhra region, rather it was initiated by the people of Telangana region, or, you may call by the people of the State of Hyderabad. And, the growth rate in the region of Telangana, since integration, in the field of education, health care, irrigation, employment, etc. is very high. I was very surprised that even my learned friend, Shri Prakash Javadekar, also spoke about the political points, about political promises, about political possibilities and about political opportunities.

But nowhere did he mention in his spirited speech as to in what sectors a particular region is backward, in what sectors a particular sector is deprived of development, and in what sectors there is law and order problem or any other discrimination. Sir, he talked, in detail, about the political movements and political understandings only. Sir, in the recent years, the growth rate in some parts of Andhra region is lower than that of some parts in the Telangana region. In some sectors, some of the areas in Telangana have excelled over Andhra region. From this also, it is evident that this is an unjustified demand. If the area is really deprived, if the area is really exploited, then, there is nothing wrong in a political party or organisations demanding for a separate State; we fully support that. But these are all political demands. Let this august House rethink

over whether it will be proper on our part to do that kind of a division. Sir, for some political gains and for some short-term gains, provoking the youths, innocent students, the down-trodden people and employment organisations to come to the streets, make *hartals*, cause extensive damage to the public and private properties and attack innocent citizens, create law and order problem and stall the development, is not justified on the part of any civilised society. Sir, the demands which are justified can be fulfilled with public support. By educating the public as to what they are being deprived of, this can be done, Sir. But rising emotions, rising petty regional feelings should not be encouraged by this August House. We will be doing our society and our country a great loss by doing so. We will be doing injustice, Sir. Sir, from our party side, earlier, the Party resolved in its highest policy-making body for a second SRC and from their party side, earlier, they promised 'two States and one vote.'

Sir, now I come to some of the other points which have been raised. Our great leader, Pandit Jawaharlal Nehru, never said anything on its potentiality for a separate State, except integrating it as one, based on the First SRC.

As far as the hon. Member's argument regarding injustice done to Telangana in regard to development is concerned, I will give you the statistics—if you allow me—to show you the unprecedented development that is there in Telangana region in the fields of education, health care, irrigation, employment, tourism, etc. In regard to the aspersion made by him regarding neglect, I must mention that similar slogans were raised by many friends who belong to Telangana region, while demanding a separate State on the basis of lack of development, whereas extensive inquires, analysis, collection of statistics and data in various fields of development by various Commissions, various statistics, various Censuses, etc., are clearly showing otherwise.

Sir, my learned friend was referring to some chapter of the Srikrishna Commission Report. He was making some allegation. I really did not have the opportunity to go through the Eighth Chapter wherein he said, "management by Press or otherwise". I am not very sure about it. But the Srikrishna Commission has really done a serious study, Sir. They have toured the entire State extensively. ...(*Time-bell rings*)... Sir, this is a very sensitive issue, particularly for my State. For Prakash Javadekarji, it may be a political slogan. But, for my State, it is the question of the survival of our distinction. So, I must be given, at least, double the time than what has been given to him. I am only for time. Sir, Srikrishna Commission went throughout the State. They had given advance notices to all political parties, to the Administration, and they conducted various inquiries in Hyderabad. They met Legislators, Opposition Parties, Members of Parliament, judicial people and various political and voluntary organizations. They met them at Hyderabad. They went to all districts, not to District Headquarters alone. They went to *Taluk* headquarters and even to villages. They also went to some villages. They really conducted a very extensive study with a great deal of interest.

[DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO]

Sir, having realized the reality and the shallowness in their slogan for the demand of a separate State on the basis of development, some short-sighted leaders, who are demanding a separate State of Telangana for the short gains, are now shifting their slogan from 'backwardness' to 'sentiments and self-rule.'

Sir, I do agree that there may be certain disparities in the development of certain areas. I may bring to your knowledge that the districts of Anantapur, Cudappah, Kannur, Chittoor of Rayalseema and the districts of North-Coastal Andhra are more backward than any other districts in Telangana. So, when we wish to take up the development of a State, the entire State should be taken as a unit, and wherever there are disparities, they must be removed. I am one who strongly supports development of the backward and deprived areas.

Sir, I would recall one example from my student days. I was a student of the Gulbarga Medical College, which was in the Hyderabad-Karnataka region, and which was a part of the erstwhile Nizam area. My native place is near Vijayawada. I had to travel though Hyderabad and use different means of transport to reach Gulbarga. We were a group of friends from Telangana and we used to travel places, from Hyderabad to Mandammari, which was almost at the Maharashtra-Andhra Pradesh border. We used to travel up to that place in the late 60s and the early 70s also. Sir, I have witnessed the gradual development of the region from '70s; so must have my other friends. ...(*Time-bell rings*)... Sir, please give me some time more.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude.

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : Sir, at present, the highest rice-procuring districts in Andhra Pradesh are Karimnagar, Nalgonda, East Godavari and West Godavari regions. Procurement of rice is the highest in Telangana district. If we do not take development into account, and if we are driven only by sentiments and passions raised by different political parties, we will be doing great injustice to this country.

Sir, I am surprised about Mr. Javadekar's opinion that smaller States have better administration and efficiency and a greater access to the Government. Let us presume this to be correct. Now, when there was a demand for a separate State to be carved out of Uttar Pradesh, with a population of about 20 crores, friends would remember that his own leader, Shri L.K. Advani, had strongly objected to the division of the State of UP.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : You may conclude now. There are a number of speakers left. There are more than a dozen speakers on the list.

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : This clearly shows that they are not interested in smaller States; they can only raise political slogans. It is not out of their

conviction, or, for development. Their resolution is also a consequence of that. Sir, I would quote from a letter of Mr. L.K. Advani, the then Home Minister...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : You have already quoted it. That is enough.

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : No, Sir; there was a small discrepancy. This letter was dated the 1st of April. It reads, "Dear Narendra ji, please refer to the matter raised in the Lok Sabha on the 26th February, 2002, under rule 377, regarding the need for creation of a separate State of Telangana. I have had the matter examined."

"The Government of India is of the view that regional disparities in economic development can be tackled through planning and efficient use of available resources. The Government, therefore, don't propose creation of a separate State of Telangana. With regards. Yours sincerely, L.K. Advani." This is addressed to Shri Ale Narendra, 16, Windsor Place, New Delhi, on the Home Minister's letterhead. ...(*Time-bell rings*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : There are more than one dozen speakers. ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)...

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : Sir, if my friend thinks that there is a merit in the demand for a separate State of Telangana and it serves the cause of geographical contiguity, economic viability and administrative convenience, should this be only for Andhra? Is it not for other areas of the country? Let him demand for smaller States. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude. ...(*Interruptions*)...

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : How can it be demanded only for one State? ...(*Interruptions*)...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: How much is the time-limit for every Member? ...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh) : He is not yielding. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude. ...(*Interruptions*)...

DR. NAJMA A. HEPTULLA : Sir, I also want to speak on this issue ...(*Interruptions*)...

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : My friend from the BJP is not aware of the facts and figures and the situation prevailing in Telangana region. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You conclude. ...(*Interruptions*)...

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : Before 9th December, 2009 and immediately after ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : I have so many speakers. ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)...

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : If he wants to know the loss that is caused to the State of AP ...(*Interruptions*)...

DR. NAJMA A. HEPTULLA : Sir, how much time is there for every Member? ...(*Interruptions*)...

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : Vested interests of a few political people in AP and the political interest of the BJP ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Ramachandra Rao *ji*, please conclude. ...(*Interruptions*)...

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : You would not have brought this Private Members' Resolution. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude. ...(*Interruptions*)... There are other speakers. ...(*Interruptions*)...

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : I appeal to my friend Javadekar and to all the hon. Members of this House to understand the extensive damage caused to the development and to the people of AP ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Shri Parshottam Rupala ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)...

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : Only half-a-minute. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : There are a lot of people. ...(*Interruptions*)... Conclude within half-a-minute.

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : I appeal to my friend Javadekar and to all the hon. Members of this House to understand the extensive damage caused to the development and to the people of AP, more particularly to the suicide of the innocent. ...(*Interruptions*)... and also unimaginable damage to the development and to the law and order situation in other parts of the country. Hence, I request Shri Prakash Javadekar to withdraw his Resolution. ...(*Interruptions*)... I request all my learned and visionary friends from this House to oppose this Resolution and save this country from disunity which results in disaster. ...(*Interruptions*)... I thank the hon. Chair and all my colleagues for giving me an attention. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please take your seat. ...(*Interruptions*)...

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO : Jai Hind, Jai India, Jai Bharat.

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला (गुजरात) : महोदय, मैं प्रकाश जावेडकर जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने देश की एक बहुत बड़ी समस्या, जिससे हमारे प्रान्त के लोग लड़ रहे हैं, उस तेलंगाना सेंटीमेंट को इस अगस्त हाउस में प्रस्तुत करके इस सभा को ध्यान आकर्षित करने का काम किया है।

(उपसभाध्यक्ष (डा. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन) पीठासीन हुए)

अभी हमारे साथी डा. के.वी.पी. रामचन्द्र राव बोल रहे थे, मैं बहुत आदर के साथ उन्हें सुन रहा था। अपने भाषण में वे बताने की कोशिश कर रहे थे कि तेलंगाना राज्य बनने के खिलाफ कभी आडवाणी जी ने कुछ पत्र लिखा था, कुछ बयान दिया था। आप आडवाणी जी की डिमांड पर rely करना चाहते हैं। अगर हम आडवाणी जी के पास कोई फ्रेश निवेदन करवा देंगे तो क्या आप उस पर rely करेंगे। उस वक्त की सिचुएशन क्या थी, यह आपको भी पता है। वहां पर जो राज्य के मुख्य मंत्री थे, उनकी इच्छा थी कि वहां तेलंगाना की डिमांड पर केन्द्र की सरकार आगे न बढ़े, इसलिए ऐसा नहीं हुआ था। यह बात सब लोग जानते हैं।

यह प्रकाश जावडेकर जी का प्रस्ताव है, इसीलिए इसका विरोध करना है। आप हमेशा यही बताते रहेंगे कि भाजपा के लोग इसका political benefit लेने के लिए खड़े होते हैं। अगर हम आपके नाम पर प्रस्ताव में यह लिख दें कि इसका सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को है, तो आप तेलंगाना दे दीजिए। On behalf of the BJP, I put on record कि तेलंगाना बनाने का पूरा श्रेय हम कांग्रेस पार्टी को देने के लिए तैयार हैं, आप बना दीजिए। आपने तेलंगाना बनाना नहीं है, आपने लोगों को बनाना है। हम क्या कर रहे हैं, इस बात को छोड़ दीजिए। आपकी कांग्रेस पार्टी के सांसद लोक सभा में क्या कर रहे हैं, उसका जिक्र करो और वे आपको यहां बैठकर भी देख रहे हैं। वे तेलंगाना में जाकर भी बतायेंगे कि राज्य सभा में हमारे बैठे हुए लोग तेलंगाना के खिलाफ क्या कर रहे हैं।

सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तेलंगाना राज्य बनना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश राज्य में से तेलंगाना बनना है, इस पर हमारे में से किसी को और देश में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मगर यह आप सब को पता है कि यह राज्य हमारे देश की आजादी के साथ आजाद नहीं हुआ था। इसकी स्मृति इस गृह को होनी चाहिए, इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सासंदों को रखनी चाहिए कि यह प्रदेश हिन्दुस्तान की आजादी के बाद आजाद हुआ है। उस पर निज़ाम का रूल था और वह इस देश के साथ आजाद नहीं होना चाहता था। यह तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीति की वजह से, political will की वजह से, इस प्रदेश को भारत में मिलाने का कार्य किया, इसी वजह से वह प्रदेश देश की आजादी के एक साल बाद 1948 में आजाद हुआ था, यह historical fact है, यह सनातन सत्य है। इसका मतलब यह है कि यह ऐतिहासिक सत्य है। उसका ऐतिहासिक वजूद है और यही वजह है कि वह उसी काल से अलग प्रदेश बना हुआ है। ये उनकी फीलिंग्स हैं, इस बात को छोड़िए। ये एक आदमी, दो आदमियों से नहीं है, इस गृह में बैठने वाले सभी सांसदों को मेरी विनम्रता से प्रार्थना है कि इस तेलंगाना की मांग को लेकर 700 लोगों ने बलिदान दिया है, हम इसके बारे में कितनी फिगर्स चाहते हैं, इसको आजाद बनाने के लिए और कितनी फिगर्स चाहिए, इसके बारे में सोचिए। कौन पार्टी क्या कहती है, किस लीडर ने क्या किया है, इस बात को छोड़ो। इन 700 लोगों ने जो बलिदान दिया है, इस किसके लिए दिया है? इनकी मांग पूरी करो, इनके बारे में चर्चा करो। मैं यह नहीं कहता हूं कि पिछड़ेपन का होना राज्य बनाने के लिए कोई वजह नहीं होती है। हम भी मुम्बई राज्य

[श्री पुरुषोत्तम खोडाभाई रूपाला]

का हिस्सा हुआ करते थे, हम वृहद मुम्बई राज्य का हिस्सा थे, हमने अलग गुजरात राज्य की मांग की थी। आज गुजरात बन गया है और उस वक्त हमारे सभी नेता देख चला रहे थे। वे भी कह रहे थे कि अगर गुजरात बनेगा, तो हमारे शव के ऊपर बनेगा, तो इसका जिक्र करके उसे नहीं बनाना था, गुजरात को राज्य बनाया। आज महाराष्ट्र भी आगे बढ़ रहा है, गुजरात भी आगे बढ़ रहा है, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी महाराष्ट्र के साथ और महाराष्ट्र वालों की हमारे साथ। ऐसा कुछ नहीं है। हम भी वृहद मुम्बई राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। आज भी गुजरात में कई कानून ऐसे हैं, जिन पर Bombay Municipal Corporation एक्ट लिखा जाता है। किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप यह बात छोड़िए कि किस नेता ने क्या कहा, किस मंत्री ने क्या वचन दिया, किसने क्या वचन दिया।

सर, जुबान की क्या कीमत हुआ करती थी, इसके बारे में हमारे प्रदेश का एक किस्सा है। एक मूंछ रखने वाला आदमी बाजार में पैसा लेने के लिए गया। उसने पैसा मांगा, तो सुनार ने पूछा कि आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है, उसके पास तो कुछ नहीं था। वह दरबान था। उसने अपनी मूंछ का बाल निकालकर दिया। व्यापारी ने, स्वामी से उससे कहा कि मूंछ का बाल भी कोई गिरवी रखने की चीज़ है, यह तो टेढ़ा है। मूंछ का बाल टेढ़ा है, ऐसा वह बोला। उसने कहा टेढ़ा है, मगर मेरा है, तू रख। इसी बात पर उन्होंने उसको पैसा दिया, टेढ़ा है मगर मेरा है। यह जुबान है कोई गृह मंत्री की। हिन्दुस्तान का गृह मंत्री बोले कि मैं प्रोसेस करवाता हूं, कर देना चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है। अपनी जुबान की भी कोई कीमत होता है।

मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ observation नहीं करना चाहता। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि यह गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। मैं इस सदन के सामने सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि तेलंगाना के लोगों में जो भावनाएं हैं और उन भावनाओं के जोश में आकर लोग आत्म-बलिदानकर रहे हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। ये लोग हमारे देश का ही हिस्सा है। वहां के लोगों के भावनाओं की कद्र करते हुए, जो भी पार्टी पावर में है, उसको तुरंत ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उसको केवल वायदा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इस काम को पूरा करना चाहिए। उसको जो भी अमल करना है, खुलकर करना चाहिए। हम सबको ऐसे बिन्दुओं पर honestly अपना मत देना चाहिए। आज आंदोलन चलाने वाले लोगों को, आत्म-बलिदान देने वाले लोगों को यह लग रहा है कि देश में ऐसे नेता नहीं हैं, सरकार नहीं हैं, जो हमारी बात सुन सके और बीच का रास्ता निकाल सके। आप रास्ता निकालें, लेकिन इतना अवश्य तय करें कि वह लोगों की समझ में आए। आप ऐसे-ऐसे रास्ते बता रहे हैं, जिससे यह पता ही नहीं लगता कि नाव कहां जाएगी? समुद्र में नाव की कोई दिशा ही नहीं है। इससे लोगों में आक्रोश है। इस सदन में इस विषय पर चर्चा करने के लिए, मैं प्रकाश जावेडकर जी को फिर से बधाई देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, तेलंगाना के अलग राज्य की मांग का मामला बहुत पुराना है। बहुत से तेलंगाना समर्थकों ने इस राज्य की मांग के लिए अपनी जान तक की आहूति दी है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। लोगों की इच्छा है और क्षेत्र की जरूरत है, इसलिए यह मामला काफी समय से इस सदन में और इस सदन में भी चर्चा का विषय रहा है। सच्चाई यह है कि तेलंगाना नाम अपने आप में इतना popular हो गया है कि लोग इसको अलग राज्य समझने लगे हैं।

महोदय, हमें तेलंगाना की मांग करने वाले लोगों की भावनाओं को समझना होगा और कहीं न कहीं हमें आम आदमी की भावनाओं को समझकर, इस पर कोई सकारात्मक निर्णय लेना पड़ेगा। अलग राज्य के निर्माण का मुद्दा आज कोई पहली बार सदन के सामने नहीं आया है। हमारे माननीय सदस्यों ने सदन में इसकी जरूरत के बारे में, अपने-अपने विचार रखे हैं। मैं भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस बात को स्पष्ट करना चाहता

हूं। विकास की सही गति की परिणती, प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुस्तीकरण, रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, खेत-खलिहान मजदूर के विकास के लिए, अगर एक राज्य की स्थापना में आम सहमति बन जाती है, तो मैं समझता हूं कि यह निर्णय किसी भी सूरत में देश या जनता के विरुद्ध नहीं हो सकता है।

महोदय, अलग राज्य बनाने की मांग का यह कोई पहला मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार यह मामला आया है, इससे पहले दर्जनों अलग राज्यों के निर्माण पर, इसी सदन में मुहर लगी है। आज पंजाब अलग राज्य बनने के बाद खुशहाल है और हरियाणा राज्य भी अलग राज्य बनने के बाद ख़ुशहाल है। इसी तरह से उत्तराखंड राज्य भी खुशहाल है। मैं जिस उत्तर प्रदेश से चुनकर आया हूं, उसकी भौगोलिक दृष्टि और विशाल आबादी को देखते हुए, उत्तराखंड अलग राज्य बनाने का निर्णय भी इसी सदन के माध्यम से हुआ था।

आप उसके नतीजों पर गौर कर लें कि जिन-जिन नये राज्यों का सृजन हुआ, नये राज्यों का सृजन होने के उपरांत उन प्रदेशों में विकास की गति बढ़ी है या घटी है। अगर इसी बात का अनुमान या आकलन कर लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि एक अलग तेलंगाना राज्य बनाने पर सहमति बनाई जा सकती है। मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर, जिन्होंने भारतवर्ष का संविधान लिखा, वे इस बात के समर्थक थे कि अगर छोटे राज्य, छोटे मंडल, छोटे जिले, छोटी तहसील सृजित की जाती हैं तो विकास की गति को आगे बढ़ाने में प्रशासनिक लोगों को सुविधा होगी। महोदय, इसीलिए डॉ. अम्बेडकर की सोच को बहुजन समाज पार्टी ने ग्रहण किया और उस सोच को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो परम आदरणीय बहिन कुमारी मायावती जी ने चार बार उत्तर प्रदेश की सत्ता का संचालन किया।

महोदय, अनुभव के आधार पर, उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली के आधार पर मैं आपके बीच में यह बात रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री, बहिन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में नये मंडलों का सृजन किया, नये जिलों का सृजन किया, वहाँ नये तहसील मुख्यालय बने, जिसका सीधा-सीधा लाभ आज उत्तर प्रदेश के लोग उठा रहे हैं। उनको सस्ता, सुलभ न्याय मिल रहा है, विकास की योजनाएं आम आदमी तक पहुंच रही हैं, रोजगार की नीतियों का अनुपालन हो रहा है और आम आदमी को विकास की गति से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इस तरह के अनुभव उत्तर प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं, इसीलिए हमारी सरकार में, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री बहिन कुमारी मायावती जी ने इस बात का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधान सभा में प्रस्तावित कराया था। उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड प्रदेश बन जाने के बावजूद भी, जिसकी आबादी आज भी 21 करोड़ से ज्यादा है, यानी देश का सातवां राज्य, जोकि दुनिया का सातवां देश हो सकता है, उस उत्तर प्रदेश की आज भी उतनी बड़ी आबादी है, इसलिए इतनी विशाल आबादी को और सही विकास की दिशा से जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित करने के लिए, चार राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव केंद्र की सरकार को इसीलिए दिया था कि शायद केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए इनको चार राज्यों में विभाजित करने पर विचार करेगी।

महोदय, मैं यह मत, यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस बात की पक्षधर है कि अगर देश के अंदर छोटे राज्य होंगे तो निस्संदेह विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैंने यह पहले ही कहा कि यह कोई नई बात नहीं होगी, यह पहली बार कोई नया मुद्दा सदन के दरम्यान नहीं आया है, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे फैसले किए गए हैं, तो मैं अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी के जरिए यह बात कहना चाहता हूं कि तेलंगाना राज्य की मांग करने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं और विकास को मद्देनजर रखते हुए अगर केंद्र की सरकार उसे अलग राज्य की मान्यता देने पर विचार करती है, तो मैं नही समझता कि इसमें देश का कहीं पर कोई अहित होने वाला है।

[श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप]

महोदय, आज हमारे सामने जम्मू-कश्मीर की समस्या है। इस समस्या को कौन नहीं जानता है? विकास की नीति से अगर जम्मू-कश्मीर का आकलन किया जाए तो भौगोलिक दृष्टि से आज भी वहाँ इतनी सारी मुश्किलें हैं कि अगर जम्मू से लेह जाना पड़े तो वहाँ पर फ्लाइट के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और फ्लाइट का किराया देने के पैसे जम्मू के सभी लोगों के पास नहीं हैं। अगर कश्मीर का कोई व्यक्ति लद्दाख या लेह जाने की बात सोचता है, तो उसके पास फ्लाइट के अलावा कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, लेकिन हर आदमी के पास उतना पैसा नहीं हो सकता है। एक अनुभव और देश की जनता तथा जम्मू-कश्मीर के लोग आज भी इस बात को महसूस करते हैं कि जम्मू-कश्मीर को और आगे पुनर्गठित करके कश्मीर को अलग राज्य बना दें, तो क्या मुश्किल है, जम्मू को अलग राज्य बना दें, तो क्या मुश्किल है, लेह-लद्दाख, जो दोनों की सीमाओं से अलग हटा हुआ है, उसे यूनियन टेरेटरी बना दें।

अगर विकास को हमें जनता के बीच ले जाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को देना है, भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र की जनता को आवागमन की सुगमता देनी है, तो हमें देर-सवेर ऐसे फैसलों पर आम राय बनानी पड़ेगी। इसलिए मेरा मत है कि हमें तेलंगाना राज्य के सृजन के मुद्दे पर राजनीतिक गतिरोध को छोड़ कर, राजनीतिक असमानताओं को छोड़ कर, तेलंगाना क्षेत्र के विकास की दृष्टि से, आम राय से इस पर फैसला ले लेना चाहिए। हालाँकि, मैं यह समझता हूँ कि प्राइवेट बिल के जरिए हाऊस में एक रस्म अदायगी होती है, क्षमा करेंगे, बहुत कम मौके ऐसे आए हैं कि जब प्राइवेट बिल पर सरकार ने मजूंरी दी है, उस पर कोई कानून या नियम बना है, लेकिन अगर ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में गम्भीरता के साथ रखा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर फैसला लेने में सरकार को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। महोदय, मैं एक शेर के दो शब्द कह कर अपनी इस बात समाप्त करना चाहता हूँ।

"ये जहाँ भी अगर साथ दे, तो और बात है,
तू अगर साथ दे, तो और बात है,
यूँ तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग,
अरे, दूसरा भी अगर साथ दे, तो और बात है।"

महोदय, आज देश के पॉलिटिशियंस को, देश के नेताओं को, देश के समाज-चिन्तकों को देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए राजनीतिक टकराव को छोड़ कर मिल-जुल कर काम करने की आवश्यकता है और मिल-जुल कर ही हम इस समस्या का निराकरण करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए मेरा मत है कि हम सबको मिल कर छोटे राज्यों के पुनर्गठन पर, छोटे राज्यों के सृजन पर आम राय बनानी चाहिए, ताकि हमारे देश के लोग विकास और रोजगार से जुड़ सकें। महँगाई, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे, तमाम मुश्किलें देश के सामने आई हैं, आती रहेंगी, तमाम दिक्कतों को इस दश के लोग सह रहे हैं, सहते रहेंगे, फिर भी हम सीमित साधनों में इस देश के लोगों को जितनी भी राहत दे सकें, उसके लिए हमें खुले मन से तैयार रहना चाहिए। मैं सरकार के महानुभावों से, सरकार के नुमाइन्दों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूँगा कि आप इसे मान-प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाइए, राजनीतिक गतिरोध का प्रश्न न बनाइए और तेलंगाना के लोगों की चाहत, उनकी इच्छा और जरूरत को समझते हुए खुले दिल से इस सदन में आज यह घोषणा कर दीजिए कि तेलंगाना राज्य बनेगा, उसकी माँग को स्वीकार किया जाएगा।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, माननीय सदस्यों ने सुना, मैं दिल से बहुत मशकूर हूँ। धन्यवाद।

श्री शिवानन्द तिवारी : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक भयानक कमजोरी है कि वह अतीत से कुछ सीखती नहीं है, अतीत की अपनी गलतियों से शिक्षा नहीं लेती है। जब आन्ध्र

प्रदेश ही बना था, तो किस परिस्थिति में आन्ध्र प्रदेश बना, यह सबको मालूम है। किस तरह से उपवास हुआ, उपवास करने वाले श्रीरामुलु साहब की जान गई, उसके बाद कितना उपद्रव हुआ, लेकिन अंत में आन्ध्र प्रदेश बना। आजादी के बाद हमारे देश में जितने भी प्रदेश नए बने हैं, उन सबको संघर्ष करना पड़ा है और उसके बाद वे बने हैं, लेकिन बने हैं। हमको याद है कि बिहार में ही हमारे साथी, लालू यादव जी ने कहा था, उनका वह डायलाग बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि झारखण्ड मेरी लाश पर बनेगा। अंततोगत्वा ऐसी परिस्थिति आई कि उनकी सरकार ने खुद ही अलग झारखण्ड बनाने का प्रस्ताव पेश किया। हम लोगों ने हमेशा देखा है, पंजाब में भी जब बँटवारा हुआ, हरियाणा अलग हुआ, उस समय क्या-क्या तमाशा नहीं हुआ, किस तरह से उपद्रव नहीं हुए। अंततोगत्वा अभी आन्ध्र प्रदेश की जो हालत है, वह हालत ऐसी नहीं है कि उसको आप लंबे समय तक जारी रख सकें। आपको फैसला लेना होगा। हमको याद है कि सभी कुछ दिन पहले हिन्दू अखबार में एक कार्टून छपा था। मुख्य मंत्री, किरण रेड्डी साहब दिल्ली आए हुए थे, यहाँ प्रधान मंत्री जी से मिलने के लिए, सोनिया जी से मिलने के लिए घूम रहे थे और वहाँ की परिस्थिति के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो एडिटोरियल पेज पर एक कार्टून बना था कि वे मंच पर सबको दिखा रहे हैं, प्रधान मंत्री जी को, सोनिया गाँधी जी को, और लोगों को, सामने बेचारे किरण रेड्डी जी बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहा है कि आन्ध्र प्रदेश में आगजनी हो रही है, लूट हो रही है और तेलंगाना के 'एन' को गायब करके कार्टूनिस्ट ने बनाया था—तेलंगाना।

यानी मंच पर लोग गाना गा रहे हैं और तेलंगाना जल रहा है। वहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और यह भ्रम की स्थिति आपने खुद ही पैदा की है। जब आपने श्री कृष्ण कमिशन बनाया, उस समय गृह मंत्री जी ने जो घोषणा की, उससे यही संदेश गया। हमारे जैसे आदमी ने भी यही समझा कि अब सरकार तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का फैसला ले चुकी है, इसीलिए गृह मंत्री जी ने इस तरह का बयान दिया है। उसके बाद भी आपने मामले को लटका कर रखा है। यह स्थिति कैसे चलेगी? इस तरह से देश नहीं चलता है। आप अतीत से सीखिए। जब गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ था, उस समय भी कितना हंगामा हुआ था। उस समय भी नेताओं ने पूरे महाराष्ट्र को एक रखने की कोशिश की थी।

हमको याद है, 1952 में जब देश का पहला चुनाव हुआ था, उस समय इस देश के जो वित्त मंत्री थे, सी.डी. देशमुख साहब, उन्होंने इसी सवाल पर 1956 में इस्तीफा दिया था। अन्तोगत्वा उन्हें गुजरात को अलग राज्य बनाना ही पड़ा। अब तेलंगाना को भी अलग बनाना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि आप इसे किस कीमत पर अलग राज्य बनाना चाहते हैं? आप इतनी कीमत लेकर मत बनाइए कि आन्ध्र प्रदेश बर्बाद हो जाए। हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप अपने विवेक को जगाइए और इतिहास से, अतीत से शिक्षा ग्रहण कीजिए। आप यह मान कर चलिए कि अब उस इलाके की जनता स्वयं यह चाहती है। वहां जो पब्लिक ओपिनियन है, वह इतना आक्रामक ढंग का है कि जो तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध कर रहे हैं, वे उस इलाके में नहीं घूम सकते हैं, वहां ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है। आप कितने दिनों तक इस परिस्थिति को कायम रखना चाहते हैं?

हमारी गुजारिश है कि आप साहस कीजिए। इसमें आपको कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं होने वाला है। हमने देखा है कि कोस्टल एरिया में, जहां आपकी पार्टी के विधायक की वजह से सीट खाली हुई थी, वहां भी जगन रेड्डी की पार्टी वाला आदमी जीता। अभी फिर वहां कोस्टल इलाके में एक लम्बा-चौड़ा उप चुनाव होने वाला है। उस चुनाव का नतीजा भी आप देखिएगा, वह भी आपके खिलाफ जाएगा। इसलिए राजनैतिक तौर पर भी आपको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है।

हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप और ज्यादा विनाश मत करवाइए, साहस कीजिए और तेलंगाना को अलग राज्य बनाइए। इसके अलावा आपके सामने कोई और रास्ता नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal) : Sir, there is a saying in English, "Small is Beautiful". But, it does not mean on the contrary that large is ugly. Sir, if you look at the history of creation of Andhra Pradesh, Potty Sreeramulu died for creation of Andhra Pradesh from Madras Presidency. But, when he died, he died for *maha* Andhra Pradesh which included Telangana. I am not disputing the right of the Telangana people to have their separate State. They have every right to do so. I am not opposing it and I will not oppose it except that I will also support it on the other ground that if the Central Government, as it has been said, agreed 'in principle' as late as 2009, then, even after change in circumstances, the word should be kept. There is no denying it.

My other point is that I salute the struggling spirit of Telangana people not for what they are doing today. I salute their struggling spirit when they fought against Nizam and when they fought against Razakars. They fought for the independence of India. They fought for *Jai Bharat*, one India. So, they have been fighting for that. Same Telangana people fought against feudalism, the Deshmukh feudalism, in the Telangana region. In fact, the first move for land reforms in India started in Telangana. People do not know that. They sacrificed. Then, Pandit Nehru took up the whole movement as a Congress Party programme and land reforms became a part of the Congress manifesto. I am not going into that. So, the people of Telangana have fought. They will fight, and fight ceaselessly, till they get what they demand.

As I said earlier, not necessarily agree. Today Telangana is much more developed than what it was during the Nizam State. They have a right to form a new state but you cannot deny the combined resources of Andhra Pradesh have helped them to reach the position which they are in today. So, my earnest request to both the sides is don't raise emotions, sit down together and come to an amicable settlement. If you think they have a right, if you think it can be viable, allow them to have a viable State. Then, there is no question. If you think that you can accommodate their desire or autonomy within Andhra Pradesh, then, try to find it out. But don't take a position in which I am right and you are wrong; and you have a *dharam yudh* in Kurukshetra. No, don't do that. As has been said by previous speakers, there had been a fight for division of Maharashtra and Gujarat. Both are prospering. There was a fight for creation of Andhra Pradesh from Madras State. Now, Andhra Pradesh is the rice bowl of India; and most highly skilled IT personnel come from that State. In fact, if all the NRIs of Andhra Pradesh working in Seattle come back, American system would collapse. They are from coastal Andhra and Telangana region. So, if there is an emotion, I would only request don't be guided by emotions, go by facts that are needed for further development or it is only because few people want to get share in power. As a principle, I have nothing against it, but I do appeal to both Andhra leadership and Telangana leadership to have a second look and think you cannot stay together, then go apart, but live peacefully. Thank you.

श्री देवेंदर गौड टी. (आन्ध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, तेलंगाना जैसे एक अहम मुद्दे पर मुझे बोलने के लिए आपने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

4.00 P.M.

महोदय, अभी जावडेकर जी तेलंगाना पर जो resolution लाये हैं, उस पर अभी तक मैं सब लोगों की राय सुन रहा था। मुझे एक बात की खुशी है कि सारे लोग इस बात की अच्छी जानकारी रखते हैं कि तेलंगाना में क्या हो रहा है और तेलंगाना के लोग क्या चाहते हैं। सारे जिम्मेदार लोगों को, सब को इसकी जानकारी है। They have very good understanding of what is going on in Telangana. यहाँ पर यह पहली मर्तबा नहीं है। इसी August House में कई बार इसके बारे में चर्चा हुई, मगर आज मैंने सोचा कि आपके सामने अपने विचार रखने का यह मेरा पहला मौका है। मैंने सोचा कि मिनिमम होम मिनिस्टर साहब तो रहेंगे, तो कम-से-कम इसमें हमें कुछ-न-कुछ जवाब मिल जाएगा। मगर, यहाँ पर तो कोई जिम्मेदार आदमी या जिम्मेदार मिनिस्टर, I don't think you are going to respond.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JITENDRA SINGH) : I am here. I am going to reply on behalf of the Government.

श्री देवेंदर गौड टी. : मगर यह तो एक ऐसा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि अजीत सिंह साहब तो इससे बहुत वाकिफ हैं, मगर I do not know whether you are going to speak on behalf of the Government. तेलंगाना आज की डिमांड नहीं है। बहुत सारे लोग यही समझ बैठे हैं कि तेलंगाना नामक एक सेपरेट स्टेट के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। यह एक गलतफहमी है। हम लोग एक सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं। We are demanding de-merger of the State. तेलंगाना जब बना था, उस वक्त यह कंडीशनली बना था। यह gentlemen's agreement होने के बाद ही बना था। मुझे यह बताइए कि पूरी इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे स्टेट्स बने, at the time of formation of States, was there any agreement between the States?

मगर वहां हमारे साथ वैसा नहीं हुआ। पहले ही हमारे ही घर में आकर हमको ही assurance दिया गया कि कि आपको सेफ रखेंगे। That was the overall crux of the agreement at that time. 1947 में भारत को आज़ादी मिली, मगर we were all under the Nizam's rule at the time. उस समय निज़ाम ने Indian Union में मिलने से refuse कर दिया, क्योंकि वह खुद को independent nation रखना चाहता था। उस समय हम लोग यानी हैदराबाद स्टेट के लोग वहां पर लड़े, the Armed Struggle was a world famous Armed Struggle where 4,000 people died. उसके बाद जब Sardar Vallabhbhai Patel ने एक निर्णय लेकर Indian Army को भेजा, तब within 24 hours the Nizam surrendered to the Army. It is not because of the strength of the Indian Army. I want to clarify it. It was because he was not having control over Telangana by that time itself. All the people were agitating and we welcomed the Indian Army and within 24 hours he surrendered before the Indian Army. उस समय हम लोगों ने जज्बा दिखाया। हम लोग यह समझे कि हम लोगों को कई सालों के बाद आज़ादी मिली है, we will be free now; we will enjoy the fruits of freedom now. तब जाकर 1952 में हैदराबाद स्टेट बनी। हैदराबाद स्टेट में first election हुए। उसके बाद our own Chief Minister was elected. Mr. Burgula Ramakrishna Rao was a very popular Chief Minister. Somebody was mentioning ithere. You take the decisions of that Government. Very popular Acts were made at that time. Take, for example, the Tenancy Act. I was also the Revenue Minister for four or five years in Andhra Pradesh and the Supreme Court also commended that this was one of the progressive Acts made by the then Hyderabad Government. Then there are the Protected Tenancy Act,

[श्री देवेंदर गौड टी.]

land reforms, etc. We were fortunate कि दो नदियां, कृष्णा और गोदावरी हमारे यहां से गुजरती है, उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग प्लान बना रहे थे, और सब काम कर रहे थे। उसके बाद 1956 में प्रथम SRC बैठी। Fazal Ali Sahib ने उस समय clearly mention किया था कि प्रथम SRC में भी यह नहीं कहा गया कि Telangana or Hyderabad State को आन्ध्र में मिलाना चाहिए। उन्होंने clearly mention किया कि let the election go. एक election होना चाहिए, उसमें Telangana Assembly में resolution होने के बाद अगर तेलंगाना असेम्बली चाहती है, then only you must merge with Andhra. जब तक नहीं चाहती है, तब तक मर्ज नहीं करना चाहिए। मगर उस समय हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं था। जब 1953 में आन्ध्र स्टेट बनी, मद्रास से अलग होने के बाद, आन्ध्र स्टेट बनने के बाद वहां के लोग मद्रास, जो कि आज चेन्नई है, को उसकी राजधानी बनाने के लिए लड़ रहे थे। पोट्टी श्रीरामुलु साहब की जान इसी में गई थी। मगर उस समय केन्द्र सरकार यह निर्णय नहीं ले सकी। उस समय Rajagopalachari जैसे स्टालवार्ट थे, ultimately it went to Madras. वह चेन्नई तमिलनाडु में चला गया। मद्रास को राजधानी नहीं बनाया गया। वे Kurnool को राजधानी बना कर वहां पर चला रहे थे। There were no proper buildings. Believe me, only under tent Secretariat was running. उस समय दबाव आने के बाद Central Government, the Congress Party, at that time forcibly हैदराबाद को राजधानी बनाने के लिए, under their pressure हमको मर्ज किया गया। We were not willing at that time also. उसके बाद gentleman's agreement बनाए। एक भी एग्रीमेंट का एक भी हिस्सा लागू नहीं हुआ। Within one year वह पूरा खटाई में डाल दिया गया। They never honoured anything. लोग agitation पर agitation करते गए। उसके बाद 1969 में बहुत बड़ा agitation हुआ।

चार सौ लोग पुलिस फायरिंग में मारे गये। इंडियन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था। 400 people were killed in police firing. I was very young at that time. I also participated in that movement. चार सौ लोगों के मरने के बाद क्या नतीजा आया? तेलंगाना मसले पर आप लोग अभी भी वही सोच रहे हैं, आप अभी भी उसी लाइन पर हैं कि It is the internal problem of the Congress Party. उस वक्त चेन्ना रेड्डी साहब, जो कि इसको लीड कर रहे थे, उन्होंने TPS बनायी। वहाँ के लोगों ने उस वक्त TPS को full majority दी। Out of 14 Parliament seats, 11 seats were won by the TPS at that time. वे बड़ी majority से जीते। उस समय आपने क्या किया? आपने चेन्ना रेड्डी साहब को manage कर लिया और उनको पार्टी में मिला लिया। उनको उस वक्त चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, पूरे एमपीज़ को लाकर आपने पार्टी में मिला लिया और किस्सा खत्म कर दिया। उसके बाद आपने कुछ फार्मूला बनाया, जिसे Six Point Formula कहा गया। हमें constitutional guarantee दी। The Constitution was amended, but it was not honoured. उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। Employment और water में वही disparity चलती रही। Again there is an agitation. Again there is an agitation for a separate State. It is still continuing in the State of Andhra Pradesh. यह सब को पता है कि पहले आग लगा दी और अब कांग्रेस वाले कुआँ खोद रहे हैं। यह पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए। वहाँ इन्होंने आग लगा दी और बैठ गये। उस वक्त सत्ता के लिए इन्होंने बहुत बड़ा नाटक खेला और आज इनको खुद यह मालूम नहीं कि कैसे इसको solve करना चाहिए। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या गलती की? I am not finding fault with my Andhra brothers. सिविल सोसायटी में हमेशा यही होता है कि कोई आदमी सहन करता रहता है, कोई educated होता है और कोई उसकी advantage लेने की हमेशा कोशिश करता है। That is a human weakness. It is with the Government of India. आप लोगों ने गलतियाँ कीं। हमने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के ऊपर हमेशा भरोसा किया और हमें आप

लोगों से धोखा मिला है। आप लोगों ने हमेशा धोखा किया है। पंडित जी उस वक्त clearly mention कर रहे थे कि यह जो शादी हुई है, आप कभी भी तलाक ले सकते हैं। He was also not willing; he was also not prepared for the State of Andhra Pradesh. But unfortunately, a lot of pressure was built on him. Ultimately, he declared in the Nizamabad meeting कि यह मुझे भी उतना पसन्द नहीं है, फिर भी आप कभी भी तलाक दे सकते हैं, कभी भी you can separate. That was also mentioned in the agreement. आज क्या हुआ है? 50 साल गुजर गये, चार सौ लोग फायरिंग में मारे गये। अभी भी वहाँ के आंदोलन में सात सौ लोग मारे गये हैं, जिनमें कई स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की है और वे अभी भी कर रहे हैं। क्या यह आपके देश के लिए कोई शोभा देता है? Is it not a black spot on the democracy of this country? I am asking this directly. यह किसी एक कंट्री की डेमोक्रेसी के ऊपर black spot है। It is nothing but suppressing the people of this area. आप वहाँ के लोगों को कुचल-कुचल कर हमारा एकदम गला काट रहे हैं। यह और कुछ नहीं, बल्कि पॉलिटिकल गेन के लिए यह सारा खेल खेला जा रहा है। आप समझते हैं कि we are not going to come to power third time, इसलिए तेलुगुदेशम् जैसी कुछ पार्टियों को वहाँ कमजोर करने के लिए - They are playing this game to get political gains. मगर, मैं आज यहाँ राज्य सभा में on record यह बोल रहा हूँ कि इलेक्शंस अब ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि इलेक्शंस करीब हैं। वक्त आएगा, बहुत जल्दी आएगा। Not even one single Member from the State of Andhra Pradesh will come to Lok Sabha this time. You take it from me. You will lose Hyderabad; you will lose Andhra and you will lose the *Gaddi* in Delhi also. आप लोग जो खेल खेल रहे हैं, वह आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। People of both the regions are not happy with the kind of approach which you are adopting. आप लोग जिस approach से आगे चलते जा रहे हैं, आप जो नाटक खेल रहे हैं, यह आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। अभी माननीय सदस्य, रामचन्द्र राव साहब इस पर बोल रहे थे।

He was the *de facto* Chief Minister at that time. He himself said, "I am the soul of Rajasekhara Reddy." I do not know where he is. After becoming the Chief Minister of Andhra Pradesh, 50 साल में हमारे साथ जितना *किया, जितना नुकसान हम लोगों का हुआ, उससे ज्यादा इनके पांच साल के रूल में हुआ है। एक तरफ हमारे यहां पानी के लिए एज़िटेशन चलता है, दूसरी तरफ हमारा पानी जबर्दस्ती, गुंडा-गर्दी करके ले लेते हैं। Forty-four thousand cusecs of water was diverted एक तरफ तेलंगाना में, पूरे Nalgonda District में पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। हमारे लोग वहां पर जहर भी पी रहे हैं। Fluorosis से किसी का हाथ नहीं, पांव नहीं; कोई आदमी चार फीट, तीन फीट से पानी लेता है और साइड से कृष्णा वाटर चला जाता है। Our Krishna water was diverted from one basin to the other basin. On what basis was this done? इस देश में कोई कानून नहीं है, कोई मकेनिज्म नहीं है इस देश में कंट्रोल करने के लिए ...(*Interruptions*)... I want my friend to reply to this question as well, if he is able to do it. I am asking. आप एक तरफ बोलते हो कि जिस्टस करेंगे, एक तरफ बोलते हैं कि हम लोगों ने तेलंगाना में बहुत डेवलपमेंट किया है। कौन से कानून से आपने tripartite बनाया। आप बताओ because you were there. You were one of the important personalities in that Government. You were almost a decision-making personality at that time. I want to know from you कौन से कानून से, कौन से तरीके से आपने बनाया। We have the legitimate right. हमें कृष्णा का वाटर मिलना चाहिए। आपने क्या किया? आपने जबर्दस्ती पूरा Forty-four thousand cusecs of water, which was due to Telangana, was diverted. अभी

---

* Expunged as ordered by the Chair.

[श्री देवेंदर गौड टी.]

जो कृष्णा का ट्रिब्युनल आने वाला है, आप देखिए, वहां कृष्णा ट्रिब्युनल में भी हमारा कोई क्लेम बतलाने वाला नहीं है। वहां पर ऐसी सरकार चलती है और आप बोलते हैं कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। पूरा पैसा वहां डॉयवर्ट किया गया है, आप लोगों को वहां पर लेकर गए। एक तरफ वहां पर एज़िटेशन हो रहा है, वहां लोग मर रहे हैं। आप बोलते हैं, आप बताते हैं कि हम लोग आपके लिए जस्टिस करेंगे। आज कौन घोषणा करेगा। अपने ही घर में हम लोग पराए हैं। यह कितना पेनफुल होता है, इसको आप सोचिए, if you are living like an outsider in your own house. We can't take any decision. We cannot even question your decision. That is the conditon of the Telengana people. Sir. That is why we are demanding a separate Telengana. Otherwise, what is the fun of it? इस 50 साल में किसी स्टेट में ऐसी कोई डिमांड है, Right from the formation of the State itself, till date, everyone, not one person,—you can misguide one or two persons— मगर आपकी यूनिवर्सिटीज में एज़िटेशन चलता है, यूनिवर्सिटीज में बच्चे मर जाते हैं। क्या वे बच्चे अनएजुकेटेड हैं, अनपढ़ हैं, उन लोगों को मालूम नहीं है कि दुनिया क्या चीज होती है? किसके लिए मर रहे हैं, क्या वे ऐसा नहीं जानते हैं? Are they really misguided people? आप कैसी बात कर रहे हैं। आप हमारे सैल्फ रूल चाहते हैं। इसीलिए कि हम जीना चाहते हैं, हम अपनी आजादी के साथ जीना चाहते हैं, with all freedom. जैसे पूरा हिन्दुस्तान रह रहा है, हम भी रहना चाहते हैं। क्या इसमें हमारी कोई गलती है? हमारे पूछने में कोई गलती है? अभी आप बतला रहे थे कि it is a स्मॉल स्टेट। It is not a small State. Already eighteen States, smaller than the Telengana area, are there in the Indian Union. वे हमारे से छोटे हैं, चार करोड़ पीपुल है। हमने feudal system से फाइट किया है। उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट आए, हजारों लोग मरते जा रहे हैं। My great leader, NTR, gave clear liberty to the people of Telengana at that time. It was only after he abolished the Patel-Patwari system, that a total freedom was there. ऐसे सिस्टम को बहुत सारे लोग, हम लोग लड़ते-लड़ते हुए आए। मेरी आपसे विनती है, यह कोई पूरा पॉलिटिकल गेम नहीं है, यह किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। या किसी individual का मुद्दा नहीं है। आपने परसों का "सकला जनुला सम्मे" देखा होगा, जिसमें हर आदमी ने वहां participate किया। हमें आखिर क्या करना चाहिए और क्या करें तो आप हमें तेलंगाना देंगे? इस में और कितने लोगों की जान जानी चाहिए, Aare there any statistics? If you want, you fulfil that one. क्या इस के लिए हजारों लोग मरने चाहिए? क्या हम लोग within this country, अलग देश मांग रहे हैं? Baba Saheb Ambedkar has said that with a simple majority a Bill can be passed. आर्टिकल 3 में यह clear cut mention किया गया है, not even a Constitutional amemdment is required for the formation of any State. It is only administrative arrangement we are asking, administrative convenience we are asking. We want self-rule. We want our own resources. We are not asking anybody. हमारे यहां कृष्णा, गोदावरी नदियां हैं। हमारे पास सिंगरौली कॉलरीज जैसी first class कॉलरीज हैं जिन में काला gold है। हमारे अच्छे किसान हैं, first class land है, अगर उसमें पानी दिया तो बहुत अच्छी क्रॉप हो सकती है। हम पानी ले आएंगे और उसके ऊपर हमारा हक भी है। आप decision-making power हमारे ऊपर छोड़िए। It is an irresponsible behaviour on the part of the Government of India, सर, आप एक बात सोचिए। हम लोग अभी बहुत peaceful agitation करते आ रहे हैं। ऐसे कई मूवमेंट्स में कई लोग मर गए। हमारे होम मिनिस्टर 9 दिसम्बर को वहां आए और announce किया कि process has started. हमने बच्चों पर चल रहे हंड्रेड केसेज खत्म कर दिए, मगर एक भी केस विदड्रा नहीं हुआ है। अभी भी बहुत से बच्चे जेल में हैं, बहुत से बच्चों के ऊपर केसेज हैं और वे कहीं नौकरी नहीं कर

सकते। कोई बच्चा नौकरी के लिए जाता है तो कहते हैं पुलिस केस है और उसे नौकरी नहीं दी जाती। ऐसे हजारों लोगों के ऊपर केसेज हैं। This kind of situation is there in Andhra Pradesh and our country is just ignoring it. और आपको, किसी को कुछ नहीं होता है! आज पूरा आंध्र प्रदेश जल रहा है। Is there any Government in Andhra Pradesh? Let me know. क्या वहां कोई काम होता है? क्या वहां कोई काम चलाने वाला है? मुझे सरकार के आधे लोग और उसके मिनिस्टर्स यहां चने खाते हुए दिखायी देते हैं।

सर, वहां पर drought situation है, वहां लोगों को पॉवर नहीं मिलती, Administration paralysed है, कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है और आप अभी तक कोई decision नहीं ले पाए हैं कि आप हमें तेलंगाना देना चाहते हैं या नहीं, यह भी बताने को तैयार नहीं हैं। आप हमें सुनने को भी तैयार नहीं है। This is an irresponsible behaviour on the part of the Government. I am very sorry. सर, मैं अपील करता हूं कि you must take a judicious decision on it. मैं आपसे यही मांग करना चाहता हूं। अगर कोई भी राज्य बनता है, जैसा कि अभी साहब ने बताया there are issues. सर, इश्यूज हमेशा रहते हैं, लेकिन आप हमारे ब्रदर्स से पूछिए कि उनका क्या प्रॉब्लम है? उनको छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? अगर उनका कोई प्रॉब्लम है तो उसे solve करने के लिए initiative लीजिए, लेकिन आप कुछ करते भी नहीं हैं और क्या करना चाहते हैं, वह बताते भी नहीं हैं! आप सिर्फ कहते हैं कि manage करेंगे, टी.आर.एस. को manage करेंगे, चन्द्रशेखर राव को manage करेंगे।* He was my colleague. उनको manage करने से आपका पॉलिटिकल प्रॉब्लम solve होता होगा, मगर Telangana problem is not going to be solved. It is not his demand. It is the demand of the Telangana people. He may be your best friend. आप उनको manage कर सकते होंगे। आपने जैसे चेन्ना रेड्डी को किया, उनको भी कर रहे हैं। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं, मगर ultimately, it is not any leader, but it is the people of Telangana who want Telangana. आप उसके बारे में सोचिए और ज्यादा देर मत कीजिए। अभी तब बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आगे चलकर और प्रॉब्लम न हो, हम भाई-भाई मिलकर अच्छी तरह से रहें, यह आपको देखना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के cooperation के साथ डेवलप होना चाहते हैं, लेकिन आप वहां की प्रजा में डिवीजन ला रहे हैं।

हमारे यहां जो फैमिलीज हैं, उन फैमलीज को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कल्चरली, everywhere you see, और आप इसको जितना पेंडिंग करते जाएंगे, उतनी प्रॉब्लम उनकी और बढ़ती जाएंगी। इसलिए मैं पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से विनती करता हूँ, you please kindly take a decision on it. Kindly introduce the Bill. We are here to support the Bill. I am telling you that we will definitely support the Bill. Kindly introduce the Bill as early as possible. We want a clear reply from the Government of India. If the hon. Minister respond to my points, I would be grateful. So, I reiterate not to delay the issue any further.

With these words, I once again thank you for giving me this opportunity. Thank you.

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम) : उपसभाध्यक्ष महोदय, तेलंगाना के बारे में जावडेकर जी जो प्राइवेट रेजोकुलशन लाए हैं, मैं तो इसका समर्थन ही करता हूँ। मैं कहूंगा कि सिर्फ तेलंगाना ही क्यों, भारतवर्ष में जितने भी छोटे-छोटे राज्यों की डिमांड की गई है, उसको कर देना चाहिए और तेलंगानाके बारे में भी भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

[श्री बिश्वजीत दैमारी]

महोदय, बहुत समय से हमारे नॉर्थ-ईस्ट में छोटे-छोटे राज्यों की मांग हो रही है, जैसे बोडोलैंड की मांग को आज 45 साल हो गए, लेकिन दुर्भाग्य ही बात है कि बोडोलैंड को देने के लिए या न देने के लिए आज तक कोई कमीशन नहीं बैठाया गया है। आज ऐसी हालत है कि तेलंगाना की घोषणा करने के बाद भी, कमीशन बैठाने के बाद भी, बहुत सारी सलाह देने के बाद भी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जितनी भी समस्या क्यों न हो, इसके लिए जितनी जल्दी हो, समाधान कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी समस्या रहेगी, तो देश की इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में रहते हुए, भारत का नागरिक होते हुए मेरा अपना एक्सपीरिएंस है कि छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लड़ते-लड़ते आज वहां के लोग भारत से अलग होकर दूसरा राष्ट्र बनाने की मांग लेकर मूवमेंट चला रहे हैं। इसलिए छोटे राज्यों की जो डिमांड है, यह बहुत ही सेंटीमेंटल है, इसको अच्छी तरह से देखना जरूरी है। हमारे यहां से जितनी भी छोटी स्टेट की डिमांड आई हैं, वे तेलंगाना जैसी नहीं हैं। वहां के लोगों की अपनी कुछ जेनुइन समस्याएं हैं। अपनी कला, संस्कृति, भाषा को लेकर वे लोग वहां दूसरों की तरह मान-मर्यादा के साथ जीना चाहते हैं। वहां के लोगों की चलने के लिए रास्ता, खेती-बाड़ी में इरिगेशन की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए हेल्थ, सेंटर्स, पढ़ाई के लिए स्कूल-कॉलेज जैसी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर वे लोग सरकार से हर समय डिमांड करते आ रहे हैं। उनकी इन डिमांड्स को न मानने के कारण अंत में पृथक राज्यों की मांग आई, ताकि पृथक राज्य बनने के बाद वहां के लोग अपने राज्यों के लिए, भले ही ये राज्य छोटे क्यों न हों, खुद इन राज्यों के डवलपमेंट के लिए, अपने इलाकों के डवलपमेंट के लिए कुछ परिकल्पना कर सकें और उसके लिए कुछ काम कर सकें। जब भारत सरकार की तरफ से इस मांग पर विचार नहीं हुआ, तो भारत सरकार के प्रति उनका विश्वास खो गया। भारत सरकार न तो वहां की समस्याओं के समाधान के लिए कोई व्यवस्था करती है, न ही वहां की जो छोटे राज्य की मांग है उसको ही मानती है, छोटे राज्य की मांग कितनी सही है, कितनी नहीं है, कितनी युक्तिसंगत है, उसको देखने के लिए किसी को जिम्मेदारी देने का काम या कोई कमीशन इसकी जांच करे, उसको भी नहीं करती है। इस तरह धीरे-धीरे सरकार के प्रति विश्वास खोकर वहां के लोग सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट होना ही अच्छा है।

हम लोग पृथक राज्य मांग रहे हैं। फरवरी, 2003 में agreement भी हुआ और under 6th Schedule, Bodoland Territorial Council का गठन किया गया, लेकिन इसके बावजूद वह छोटा सा इलाका होते हुए भी कुछ लोग Bodoland की sovereignty की demand कर रहे हैं। आज वहां विश्वास का अभाव है कि भारत सरकार ने Bodoland के लिए जितना भी कमिटमेंट किया है, वहां के डेवलमेंट के लिए जितना भी provision रखा है, उसको वह वास्तविक रूप से कर पाएंगे। Separate Bodoland State के बदले में जो Bodoland Territorial Council दी गई है, आज उसकी administrative functioning में बहुत सारी problems हैं। इन problems के बारे में बार-बार बताने के बाद भी केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। जब हम वहां की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, पुलिस के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, किसी administrative व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो यहां से सिखाया जाता है कि जब तक आपकी separate State नहीं होगी, तब तक इसको लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जब तक हमारी separate State नहीं होगी, तब तक हमारा क्षेत्र दूसरे areas की तरह develop नहीं हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि Bodoland में 4 जिले हैं और ये 4 जिले Bodoland Territorial Council की जो administrative व्यवस्था है, उसके अंतर्गत नहीं हैं। वहां के जो Deputy Commissioner हैं, यहां भारत के कई राज्यों में उनको DM कहते हैं। वहां DM का कोई काम नहीं है, लेकिन 4 जिलों में 4 DM हैं। उनके अंतर्गत 2-3 ADC हैं, इसके साथ बहुत सारे EAC हैं।

इसी तरह वहां पर लगभग 35 IAS और ACS officer हैं और वे बिना काम के बैठे हुए हैं। वे न तो वहां पर District Council की functioning की देखभाल करते हैं, न वहाँ वे Bodoland Territorial Council में उन जैसे अफसरों की नियुक्ति करते हैं, ताकि वहां की administrative व्यवस्था और डेवलपमेंट की देखभाल कर सके। न तो वहां पर्याप्त अफसर हैं,जो भी अफसर हैं, उनको काम पर नहीं लगाया गया है। यह कैसे हो सकता है? भारत सरकार ने सिविल सर्विस के इन 35 अफसरों को वहां पर बेकार बिठाकर रखा है। उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी सिर्फ law and order को देखने की है। वहां पर पुलिस दी गई है, लेकिन Bodoland Territorial Council को एक कांस्टेबल तक की ट्रांसफर या पोस्टिंग करने का अधिकार नहीं है। Bodoland Territorial Council के साथ न तो District Administration का कोई relation है, न ही police personnel का कोई relation है। तो Bodoland Territorial Council कैसे अपने इलाके को डेवलप कर सकती है? इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं, जिनके कारण Bodoland Territorial Council ने Bodoland को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, full-fledged State बनाने के लिए फिर से एक प्रस्ताव लाकर रखा है और इसके लिए आज आंदोलन चला रही है। वहां की सरकार, वहां की पब्लिक, वहां के सारे संगठन आज फिर से पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। अगर Bodoland Territorial Council देने के बाद उसकी functioning को अच्छी तरह से चलाने के लिए वहां के लोगों की बात सुनी जाती और केन्द्र सरकार की सारी concerned Ministries उनकी बात सुनतीं, तो शायद आज फिर से separate State की मांग नहीं होती।

उपसभाध्यक्ष जी, वहां बहुत तरह की समस्याएं हैं। वहां पर पर्याप्त कालेज नहीं हैं। वहां की पापुलेशन 30 लाख है, लेकिन वहां केवल 4 कालेज हैं और 20 से ज्यादा डिग्री कालेज हैं। यहां पर होम मिनिस्ट्री को इसके बारे में बताया गया। होम सेक्रेटरी ने इसके बारे में सलाह दी। इसके बाद बताया गया कि सिस्टम के हिसाब से यह Ministry of Human Resource Development या UGC के जरिए होना चाहिए। इसके बाद उन लोगों से बात की गई। सारे norms पूरे हो गए, लेकिन वहां पर grant देने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अगर UGC से फंड मिलना है, तो उसे Central University के अंतर्गत आना चाहिए। अभी Bodoland में एक भी Central University नहीं है। जब हम Central University की मांग करते हैं,तो ये कहते हैं कि असम में पहले से ही 2 Central Universities हैं, इसलिए हम और Central University नहीं दे सकते हैं।

अगर एक राज्य में दो ही Central Universities हो सकती हैं, हमें कभी भी Central University नहीं मिलेगी, तो हमें separate state दे दीजिए और नए राज्य के नाम पर एक Central University दे दीजिए। न तो हमें राज्य देंगे, न Central University देंगे। हमारे चार जिलों में जो चार डी.एम. हैं, उनको वहां की देखभाल करने के लिए न कोई जिम्मेदारी देंगे, न हमको separate state देकर वहां के लिए ऑफिसर्स की पोस्टिंग करेंगे।

सर, हमें financial powers भी नहीं दी हैं। स्टेट के ज़रिए काउंसिल को function करना पड़ता है और काउंसिल का जितना भी काम है, उसको स्टेट के लोग timely नहीं करते हैं, यह सारी प्रॉब्लम है। ऐसा बताने पर कहते हैं कि जब तक राज्य नहीं होगा, तब तक आप लोगों को financial power नहीं मिलेगी, आप बजट नहीं बना सकते हैं, राज्य या काउंसिल चलाने के लिए आप कोई financial rule नहीं बना सकते हैं। तो आप हमें राज्य दे दीजिए, ताकि हम इसको कर सकें। अगर वह नहीं देना है, तो कोई सिस्टम तो बनाइए, कुछ अमेंडमेंट तो लाइए, अमेंडमेंट लाने में क्या प्रॉब्लम है? सारे देश को चलाने के लिए आज जो existing Constitutional provision है, अगर उसमें कुछ कमी है, तो उसे सुधार दीजिए। अगर उसमें कोई समस्या पैदा हो रही है, तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि यह हमारे Constitutional provision में है, हम किसी भी समय अमेंडमेंट कर सकते हैं। अपनी सुविधा-असुविधा को देखते हुए हम अमेंडमेंट ला

[श्री बिश्वजीत दैमारी]

सकते हैं। इस प्रकार जो बोडोलैंड की समस्या है, वह बहुत genuine है, इलाकों के हिसाब से देखकर भी आप दे सकते हैं-चाहे population हो, language हो, कल्चर हो, जाति हो, resource हो, सब वहां पर हैं, पर छोटे-बड़े की बात नहीं होनी चाहिए। अगर पांच-छ: लाख आबादी में एक राज्य बनता है, तो जहां 30 लाख आबादी है, वहां आप राज्य क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं।

इसी तरह एन.सी. हिल्स एक पुराना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। वहां भी आज एक separate state की मांग उठ रही है। एन.सी. हिल्स एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उनके पास न शिक्षा की व्यवस्था है, न development की व्यवस्था है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न रास्ते की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। Plan state के हिसाब से उन लोगों को आज वहां पर फंड दिया जाता है। रास्ता बनाने के लिए भी plains के हिसाब से पैदा दिया जाता है। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी plains के हिसाब से पैसा दिया जाता है, जबकि hilly area में इतने पैसे में काम करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से वहां लोगों को न पीने का पानी मिलता है, न चलने के लिए अच्छा रास्ता है, न खेलने और एजुकेशन की कोई व्यवस्था है। वहां पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, सारे नॉर्थ-ईस्ट के hilly states में जो हमारा Election System है, उसके लिए जो constituency बनाया जाता है, पांच, दस, पंद्रह हज़ार में Assembly की एक-एक constituency है, लेकिन एन.सी. हिल्स, जो Sixth Schedule में असम का पहाड़ी जिला है, उसमें डेढ़ लाख वोटर्स के होते हुए भी सिर्फ एक ही constituency है। उसमें जो MLAs हैं, उनके area development के लिए डिपार्टमेंट के जरिए उनको allocation के हिसाब से जितना फंड मिलता है, डेढ़ लाख population वाले ये hilly areas में भी उतना ही फंड मिलता है। अगर आपको plains में कुआं बनाने के लिए बीस हज़ार रुपया मिलता है, तो hills में भी आपको बीस हज़ार रुपया मिलता है। तो वे कैसे करेंगे? Plains में रास्ता बनाने के लिए किसी स्कीम में जितना रुपया मिलता है, hills में भी उतना ही मिलता है, लेकिन आप hills में इतने रुपए से कैसे रास्ता बनाएंगे? ये सारी practical problems हैं और इनको अगर हम समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए कुछ special व्यवस्था नहीं करेंगे, अगर वहां जाकर नहीं देखेंगे, सिर्फ उन लोगों को यह कहेंगे—"बिना कारण, बिना वजह, बिना मतलब ऐसे ही वे लोग हंगामा करते रहते हैं"—तो, ऐसा बोलने का क्या मतलब है? इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि तेलंगाना की तरह जैसे दूसरे लोग छोटे-छोटे राज्य मांग रहे हैं, उनकी डिमांड को भी देखना चाहिए, specially बोडोलैंड को देखना चाहिए। यह बहुत पुरानी डिमांड है, genuine भी है और वहां के development को ध्यान में रखते हुए बोडोलैंड को जल्दी बनाना चाहिए। इस प्रकार नॉर्थ-ईस्ट की समस्या बहुत गंभीर है और इस प्रकार की छोटी-छोटी समस्याओं को गुरुत्व देना चाहिए।

सर, आज मेघालय में भी गारो लोग separate state की मांग कर रहे हैं, उनकी तरफ भी देखना चाहिए कि उनकी असली समस्या क्या है? ठीक है, पहले हम लोग बाहर नहीं जाते थे, किसी भी देश के साथ हमारा सम्पर्क नहीं था, लेकिन आज हमारे बच्चे बाहर भी जाते हैं, बाहर पढ़ते भी हैं, बाहर के साथ हमारा सम्पर्क भी है, लेकिन धीरे-धीरे हमारे भारत की जो administrative व्यवस्था है, उस पर से विश्वास खो रहा है। आज हम यहां पर चीन या म्यांमार की बात करते रहते हैं, भूटान से आज तक हमें कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों के साथ वे लोग भी कभी जुड़ जाएंगे और आज जिनको हम extremists बोल रहे हैं, terrorists बोल रहे हैं, वे उन सारे देश, जो इंडिया को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, अगर उनके साथ जुड़कर इस तरह का कोई कार्मकांड (activity) अपनाएंगे, तो हमारा देश कैसा हो सकता है?

आज बिना पढ़ाई लिखाई के होते हुए भी नॉर्थ-ईस्ट के लोग बंगला देश के साथ संपर्क करके आन्दोलन कर रहे हैं, आज वे म्यांमार के साथ संपर्क करके आन्दोलन कर रहे हैं, चीन के साथ संपर्क करके आन्दोलन

कर रहे हैं। कल जो हमारे आधुनिक लड़के-लड़कियां, जो पढ़े-लिखे होंगे, वे लोग जब इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की क्या समस्याएं हो सकती हैं, इस बात की चिंता हम लोगों को होनी चाहिए। यह समस्या क्या थी? यह समस्या बहुत छोटी-सी समस्या थी। इस समस्या को हम लोगों के द्वारा इधर से, दिल्ली से अच्छी तरह से नहीं देखा गया, जिसके कारण आज यह सबसे बड़ी समस्या बनने जा रही है। इसलिए मैं request करता हूं कि तेलंगाना को बनाना चाहिए, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। अगर छोटी-छोटी ऐडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं होंगी, तो लोगों का ऐडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छी तरह से संपर्क हो सकेगा, जितनी भी डेवलपमेंट की व्यवस्था वहां पर ली जाएंगी, उसको पाने का ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा। इसलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं क्योंकि बड़ा राज्य होने के कारण आज हमारी पहचान करने में भी मुश्किल हो रही है। आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों से यहां पर पासपोर्ट मांगा जाता है, मुझसे स्वयं से पासपोर्ट मांगा जाता है। अगर हम चीन में जाएं तो हमसे पासपोर्ट नहीं मांगते हैं पूछता है कि are you not Chinese? अगर हम म्यांमार में जाएं तो हम लोगों को वहाँ पर पासपोर्ट नहीं चाहिए। अंदर अगर किसी तरह से घुस भी गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अगर आप थाईलैंड जाएं तो वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां हमारे देश में हम एक-दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं।

इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आज यहां पर जो बिल लाया गया है, इस पर सरकार अच्छी तरह से चिंता करे और इसी तरह की अन्य राज्यों की भी जो समस्याएं हैं, उनको भी इसी के साथ जोड़कर उनके बारे में चिंता की जाए। तेलंगाना की तरह बोडोलैंड की जो समस्या है, डिमा हसाओ की जो समस्या है, गोरखालैंड की जो समस्या है, उन सबकी समस्याओं को भी एक ही नज़र से देखा जाए और उनके लिए कोई कमीशन बिठाया जाए, जो यह देखे कि सारी सेपरेट स्टेट्स की डिमांड्स जरूरी हैं या नहीं। उनकी समस्याओं का समाधान सेपरेट स्टेट दिए बिना भी किया जा सकता है या नहीं, यह सब भी देखा जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि जो हम लोग बोल रहे हैं, वह ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कि हम लोगों की शिकायतों को देखें। छोटी-सी समस्याओं के बारे में भी अगर हम यहां पर बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि सेपरेट स्टेट न होने की वजह से आप लोगों को यह नहीं मिलेगा। इस प्रकार सेपरेट स्टेट मांगने के लिए किसने हमें encourage किया? हमें दिल्ली ही encourage कर रही है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को आज फिर दिल्ली encourage कर रही है कि अगर यह चाहिए तो आप लोगों की अलग स्टेट होनी होगी, बिना स्टेट के आप लोगों को यह नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ स्टेट ही अगर उपाय है तो हम लोग स्टेट नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? इसके लिए हमारे जो constitution का existing provisions हैं, उन्हें अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करना चाहिए। अगर सबको एक नज़र से देखने में समस्या आ रही है तो उसमें अमेंडमेंट लाया जाए, ताकि कम से कम समय में हम लोग इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकें, देश में शांति ला सकें और एक साथ मिलकर उन्नति का काम कर सकें। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री भगत सिंह कोश्यारी (उत्तराखंड) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, तेलंगाना के संबंध में आदरणीय प्रकाश जावेडकर जी जो प्रस्ताव लाए हैं, रेज़ोल्युशन लाए हैं, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। तेलंगाना के विषय में प्रकाश जावेडकर जी बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाल चुके हैं - उनका नाम भी "प्रकाश" है और उन्होंने इस पर अच्छा प्रकाश भी डाला है। टीडीपी के हमारे सहयोगी मित्र ने तो - ऊपर-नीचे, आगे-पीछे - बहुत अच्छी तरह से तेलंगाना के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है। इसलिए मैं तेलंगाना के इतिहास में बहुत अधिक नहीं जाउंगा और बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, मैं उत्तराखंड से आता हूं। अभी हमरे बिश्वजीत दैमारी जी बोडोलैंड के विषय में बोल रहे थे। मैं भी एक छोटे राज्य से आता हूं। आज से केवल 12 वर्ष पूर्व यह छोटा राज्य बना था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना था। उस समय, सन् 2000 में उत्तरप्रदेश की जनसंख्या 15 करोड़ थी, आज वह 19 करोड़ से ऊपर हो गयी है, जबकि उत्तराखंड अलग हो

[श्री भगत सिंह कोश्यारी]

गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्राजील, रूस, पाकिस्तान - इन सबकी जनसंख्या को भी मिलाया जाए तो उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है। इस तरह से हमारे देश के अंदर आज राज्यों की यह स्थिति है। हमारे माननीय मंत्री माननीय अजीत सिंह जी उधर बैठे हैं। ये भी बार-बार कहते रहते हैं कि हरित प्रदेश होना चाहिए। अब ये मंत्री बन गए हैं तो बोलना छोड़ दिया है, लेकिन जब तक ये मंत्री नहीं थे, ये भी हरित प्रदेश बोलते रहते थे और कहते थे कि उत्तर प्रदेश के और टुकड़े कर दो। अभी हमारे बसपा के मित्र बोल रहे थे, मायावती जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के चार भाग हो जाने चाहिए।

यानी कहीं न कहीं मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक प्रकार से **...(व्यवधान)...**

श्री नरेन्द्र बुढानिया (राजस्थान) : आपके क्या विचार हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री भगत सिंह कोश्यारी : मैं उसी पर आ रहा हूं, आप क्यों चिंता कर रहे हो। मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। मैं बहुत छोटे-छोटे तथ्य देकर आपके सामने अपनी बात कर रहा हूं। जब उत्तराखंड बना, उसके बाद कितनी प्रगति हुई है। जो नरेन्द्र जी बोल रहे हैं, यह उनकी समझ में आएगा। वर्ष 1999-2000 में उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति इनकम थी, वह 12620 रुपये थी और यह वर्ष 2009 में आकर 27515 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई और आज यह 42000 प्रति व्यक्ति है, अर्थात कहां 12000 और कहां 42000 है। इसका सीधा अर्थ है कि उतराखंड छोटा राज्य बना, तो उसका हमको लाभ हुआ। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें हैं।

(उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) पीठासीन हुए)

मैं आपको जीडीपी के बारे में बताना चाहता हूं। जहां पहले तीन-चार परसेंट भी इन इलाकों की जीडीपी नही थी, जहां पर विकास की दर नहीं थी, इसके आंकड़े मेरे पास हैं, अभी वर्ष 2011 के आंकड़े मैं नहीं ला पाया हूं। एनडीए सरकार ने तीन प्रदेश झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बनाए और इनकी विकास दर काफी अच्छी है। आज उत्तराखंड में जीडीपी 9.5 है, जो आपकी राष्ट्रीय विकास दर से भी आगे है। झारखंड में जीडीपी 8.45 है और छत्तीसगढ़ में यह 7.35 है। मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूं कि जब ये छोटे राज्य बने, तो इनका अच्छा विकास हुआ। हमारे सामने तिवारी जी बैठे हैं, इनके राज्य बिहार से झारखंड राज्य बना है। उसकी प्रगति हुई है, यह इन्हें भी अच्छा लगता है। मैं एक किस्म से उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं क्योंकि हम उसी से अलग हुए हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश अलग लगता ही नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं, जो मुझे बार-बार कहते हैं कि कोश्यारी जी, आप उत्तराखंड में हमारे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को मिला लो, मेरठ को मिला लो, बरेली को मिला लो, पीलीभीत को मिला लो। आखिर वे ऐसा क्यों कहते हैं? उनको पता है कि आज उत्तराखंड में यदि शहर में 24 घंटे बिजली मिलती है, तो गांव में भी 20 घंटे बिजली मिलती है और बगल के उत्तर प्रदेश में शायद ही 6 घंटे बिजली मिलती हो। वहां की सड़कों को लोग देखते हैं, वहां की विकास दर को लोग देखते हैं, तो उनको लगता है कि हम उत्तराखंड में जायेंगे, तो हमें फायदा होगा। इसीलिए वे छोटे राज्य की बात करते हैं, हरित प्रदेश की बात करते हैं, बुंदेलखंड की बात करते हैं, पूर्वांचल की बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि कहीं न कहीं लोग देख रहे हैं कि छोटे राज्य ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। पहले हम हिमाचल प्रदेश का नाम लिया करते थे। जब हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ, तो उस समय मुख्य मंत्री बीजेपी का नहीं था, जनसंघ का नहीं था, परमार साहब वहां मुख्य मंत्री बने थे, लेकिन उनके कालखंड में राज्य बनते ही अच्छी प्रगति हुई। आज भी हम यह कहते हैं कि हिमाचल में बहुत अच्छी प्रगति है। वहां पर कांग्रेस का राज रहा है, बीजेपी का भी राज रहा है, आज भी बीजेपी का राज है, बीच में कांग्रेस का भी राज रहा है। यह सवाल नहीं है कि राज किसका रहा है। हमारे उत्तराखंड में भी बीच में कांग्रेस का राज था और अब फिर कांग्रेस का राज आ गया है। वहां पर सवाल यह नहीं है कि किसका राज है, सवाल

यह देखने का है कि यदि छोटा राज्य बन गया, तो हिमाचल प्रदेश की कैसे प्रगति हुई, उत्तराखंड की कैसे प्रगति हुई, छत्तीसगढ़ की कैसे प्रगति हुई और झारखंड की कैसे प्रगति हो रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर 6 लाख में सिक्किम, 11 लाख में मिजोरम, 13 लाख में अरुणाचल प्रदेश बन सकते हैं और अभी गोरखालैंड वाले गोरखालैंड की बात कर रहे थे, बोडोलैंड वाले बोडोलैंड की बात कर रहे थे, इसलिए इसको सही तरीके से देखा जाए। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हैं, राजीव जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस पर जल्दी से जल्दी मंथन करिए, जल्दी से जल्दी विचार करिए। हमें काफी बलिदान देने के बाद उत्तराखंड मिला है, इसलिए वहां पर ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तेलंगाना की क्या हालत है, काफी लोग वहां पर मर गए हैं, काफी लोग वहां जेलों के अंदर बंद हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे तो ताज्जुब होता है कि यहां की सरकार कैसी है। हमारे देश का होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलकर जाता है। It is in the process. The process has begun. Where has it begun? When did it begin? Where is it now?

क्या चीज है कि यहां आखिर एक जिम्मेदार आदमी बोलकर जाता है और अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि यह तो हमारे साथ धोखा हो गया। आप इतने पुराने व्यक्ति हैं और इतना अच्छा बोल रहे थे। आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आज शेक्सपियर जिंदा होता तो वह कहता, 'betrayal' thy name is Congress या 'Congress' thy name is betrayal. यह बोलता हूं और यह तो इनका काम है। यह कांग्रेसी इतनी बड़ी पार्टी है, जिसको गांधी जी ने सींचा। इसमें सरदार पटेल थे और नेहरू जी थे, अगर ये ठीक रास्ते पर होते, देश को अगर ठीक से चलाया होता और समय पर सही कदम उठाते तो क्या देश को ऐसा देखना पड़ता? आखिर इसमें एक से एक बलिदानी लोग हुए हैं और एक से बढ़कर एक त्यागी लोग भी हुए हैं, लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है, मुझे तो देखकर ताज्जुब हो रहा है। मैं यह चाहता हूं कि बहुत जल्द गोरखालैंड भी बनना चाहिए। उसकी अपनी परिस्थितियां हैं, उसकी अपनी भाषा है और उसकी सब चीजें अपने स्थान पर हैं। मैं जब लेह-लद्दाख में जाता हूं, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना समय लग जाता है। जब आप श्रीनगर से जाते हैं, आप जानते हैं कि बाई कार जाने पर, आपको पहले तो जम्मू से श्रीनगर जाने में ही कितने घंटे लग जाते थे? अभी कोई साथी बता रहे थे कि फ्लाइट और हेलीकॉप्टर से तो शायद ही हम में से वहां कोई जा सके, चलो हम तो MP हैं, चले भी जाएं, लेकिन सामान्य आदमी तो जा नहीं सकता है। जब आप लेह पहुंचते हैं, तो आपको लेह जाने में 500 किलोमीटर जाना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि आप 500 किलोमीटर जाने के लिए 24 या 30 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे, तो आपको जाने में कितना समय लगेगा? इसका अर्थ यह है कि उसकी परिस्थिति कैसी है? लेह, श्रीनगर से साढ़े चार सौ या पांच सौ किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर अगर आखिरी गांव डेम चोक है और जिसकी आबादी भी मुश्किल से पचास घर है, मैं वहां जाकर देखता हूं कि हमारी क्या स्थिति है? जो हमारा म*नरेगा* है, जो बॉर्डर एरिया डिवेलपमेंट प्रोग्राम है, उससे अगर वे वहां पर पैदल रोड बनाना चाहें, तो वह नहीं बना सकते, क्योंकि चाइनीज़ रोक देते हैं। आप वहां पर चाइना की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनी देख सकते हो और बड़ी-बड़ी सड़कें भी हैं। वहां जाकर हमें अपने देश की हालत को देखकर रोना आता है। वे कहते हैं कि हमें ज्यादा कुछ न देकर केन्द्र शासित प्रदेश ही दे दो। आप तो वह भी नहीं देंगे आप तो उनको यूनियन टेरेटरी देने को भी तैयार नहीं हैं। हम कब देंगे, जब बिल्कुल ही ऐसी स्थिति हो जाएगी, जैसा अभी हमारे साथी बता रहे थे कि म्यांमार में चले जाएं या चाइना में चले जाएं? तो किस कारण यह स्थिति है?

अभी आप विदर्भ की हालत देखिए कि वहां पर किसान मर रहे हैं। वहां सिंचाई के लिए पानी नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे तेलंगाना है, विदर्भ है, मैं सोचता हूं कि जनसंख्या के लिहाज से दोनों ही अपने राज्यों के फिफ्टी-फिफ्टी परसेंट हैं। ये इतने बड़े-बड़े राज्य हैं। मैं सोचता हूं कि जैसे आन्ध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है, इन सबकी आबादी भी दस करोड़ या साढ़े नौ करोड़ है। जब इतनी बड़ी जनसंख्या है और आपने यदि उसके दो आधे हिस्से कर दिए तथा राज्य

[श्री भगत सिंह कोश्यारी]

smooth चल रहा है, प्रशासन ठीक चल रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपको रोज-रोज कोई परेशान करे? ऐसा लगता है कि आपको आदत पड़ गई है कि लोग हर रोज आंदोलन करते रहें और आप लाठी चलाते रहें तब पता लगे कि कहीं कांग्रेस सरकार भी है, यूपीए की सरकार भी है, शायद आप वहां यह दिखाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा निवेदन है कि आज प्रकाश जावेडकर जी तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का जो proposal लाए हैं, इस बारे में मेरा आपसे स्पष्ट कहना है कि आप उसे स्वीकार करें। मुझे तो यह सब देखकर ताज्जुब होता है। अभी ये बता रहे थे, 'gentleman agreement' **...(व्यवधान)...** They don't stand for '‘gentleman', they stand only for one 'gentlewoman'. I have all respect for her and for all these people. मैं यह without regard नहीं बोल रहा हूं। यह क्या है? मुझे लगता है कि 'gentleman' है ही नहीं, अगर होता तो agreement को पूरा करता। आप उदाहरण देंगे कि आडवाणी जी ने क्या कहा। अच्छा, आडवाणी जी ने 2002 में या 2001 में कहा कि आज हम नहीं बना सकते, लेकिन आज तो आडवाणी जी कह रहे हैं।

आप आडवाणी जी की चिट्ठी दिखा रहे हैं कि, yes, Advaniji wrote to Mr. Narendra on such and such date, लेकिन आज जब आडवाणी जी कह रहे हैं, तो आज आप इसको क्यों नहीं बना रहे हैं? अगर आप आडवाणी जी के हिसाब से चलते हो, उन्हीं की मानते हो, तो आप तेलंगाना प्रदेश क्यों नहीं बना रहे हो? इसका सीधा अर्थ यह है, मुझे यह विशेषकर लगता है कि कुल मिलाकर हम सब लोग, एक प्रकार से हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसमें जो गंभीरता होनी चाहिए, आज वह गंभीरता नहीं है। हम माननीय मनमोहन सिंह जी का बहुत आदर करते हैं, जब उन जैसे व्यक्ति प्रधान मंत्री हों, तब यह अजीब लगता है, मैंने यह कहीं नहीं देखा है कि कांग्रेस के लोग ऐसा व्यवहार करें। मैं उत्तराखंड विधान सभा में सदस्य था, मैंने वहाँ भी अजीब चीज़ देखी। वहाँ कांग्रेस के एम.एल.एज. ने नारायण दत्त जी को तीन दिन तक बोलने ही नहीं दिया, कार्य चलने नहीं दिया। यहाँ मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री हैं, पर आपने हाउस में कितने दिन हल्ला किया, कितना हंगामा किया? आप यहाँ हंगामा करो, अपने सदस्यों को सहन भी कर लो, लेकिन हंगामा करने के बाद वहाँ राज्य भी नहीं बनाओ। ऐसा न करके, यह तो आप एक प्रकार से यह कह रहे हैं कि चोर से कहो चोरी करो और मालिक से कहो सावधान रहो। यह तुम्हारा कौन-सा नियम है? यह आप किस नियम के आधार पर चल रहे हैं? कहीं न कहीं पर, कोई तो ऐसी गंभीरता होनी चाहिए, ऐसी seriousness होनी चाहिए, एक प्रकार से thinking की कोई profundity होनी चाहिए, जिसके कारण एक दूर दृष्टि होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं लगता है कि हमारी कोई दूर दृष्टि है।

आज हमारे तीन स्टेट बन गए, लेकिन जो तीन स्टेट बने, उनका क्या नुकसान रहा? उनको भी लाभ हो गया और जो दूसरे प्रदेश हैं, उनको भी लाभ हो रहा है, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर पूरा छत्तीसगढ़ अलग नहीं होता, तो आज पूरा का पूरा मध्य प्रदेश बजाय प्रगति करने के केवल नक्सवादियों से लड़ता रहता, क्योंकि यह एक कम्बाइन्ड समस्या थी, जोकि अब केवल एक प्रदेश में रह गई। आज अगर बिहार और झारखंड नहीं होते, तो झारखंड की जो समस्या है, वह बिहार की समस्या बनी रहती और एक प्रकार से इतना बड़ा स्टेट, वह इसमें केवल इसलिए इन्वॉल्व रहता **...(व्यवधान)...** प्लीज मुझे बोलने दीजिए **...(व्यवधान)...** Please Hanumantha Raoji, don't become *Hanuman* here. Please Hanumantha Raoji, don't become Hanuman here. I am not Rama.

श्री वी. हनुमंत राव (आन्ध्र प्रदेश) : आप ही **...(व्यवधान)...**

श्री भगत सिंह कोश्यारी : आप क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं राम थोड़े ही हूं, जो आप स्टैंड हो रहे हैं। **...(व्यवधान)...** please be seated. Listen to me peacefully. I am not speaking anything

against anyone. Don't become *Hanuman.* Don't become my *Hanuman.* I don't need such *Hanumans.* उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं इस सदन से निवेदन करता हूं कि आप इस चीज को अत्यंत गंभीरता से लें। आप इतना अच्छा विषय लाए हैं, हमारे टी.डी.पी. के मित्र गौड साहब इतना बढ़िया बोल रहे थे, लेकिन आप जिस प्रकार का दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं कि आप हाउस के अंदर हल्ला कर रहे हैं और वहाँ राज्य नहीं बना रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। आप किसके खिलाफ हल्ला कर रहे हैं? क्या आप बी.जे.पी. के खिलाफ, टी.डी.पी. के खिलाफ हल्ला कर रहे हैं या इनके खिलाफ कर रहे हैं? आप किसके खिलाफ हल्ला कर रहे हो, आप किसको befool कर रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैं सोचता हूं कि यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, इस देश की जनता सब जानती है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आप बहुत समझदार हैं, ये लोग आपसे थोड़ा सुन भी लेते होंगे, आप इनसे कहिए कि इस देश की जनता ऐसी है कि यह 1975 से जनवरी, 1977 तक चुप रही, शांत रही, कुछ नहीं बोली, अखबारों तक में कुछ नहीं छपा, लेकिन फरवरी 1977 तक आते-आते हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने 1971 में हमारा इतना ऊंचा नाम किया था, हम उनका बहुत सम्मान करते थे, उनको भी इस देश की जनता ने पूरी तरह से धूल चटा दी। पूरे उत्तर भारत से आप लोग कैसे सफा हो गए थे, यह आप जानते हैं। मैं आपसे फिर बोलता हूं कि यदि आप फिर से इसी नीति पर रहे, तो यह फिर होगा। **...(व्यवधान)...** मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। आप क्यों बोल रहे हैं? आप कल यह realise करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप सभी लोग अच्छी तरह से इसको समझें। इसको आप करें या हम करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, लेकिन हम सही निर्णय लें। वहाँ पर आप हों या हम हों, वहाँ कोई भी बैठा हो, लेकिन वह सही निर्णय ले। अब समय आ गया है कि जब हम लोगों को तेलंगाना बना लेना चाहिए और निश्चित रूप से इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। यदि अधिकाधिक संभव हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके साथ ही विदर्भ भी बना दें, दार्जिलिंग भी बना दें और हमारा जो लेह-लद्दाख है, जिसकी अपनी एक विशेष प्रतिष्ठा है, अगर आप उसको केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अच्छा होगा। मैं वहाँ पर गाँव-गाँव, घर-घर घूमकर आया हूं, उस इलाके में दूर-दूर तक पैदल होकर आया हूं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसा करके इस देश में एक महान योगदान देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा सत्ता दल इसको कोई prestige issue न बनाकर, प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर निश्चित रूप से जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव का या तो समर्थन करेगा या इस पर तुरंत कोई बिल लाएगा। मैं इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वी. हनुमंत राव : उपसभाध्यक्ष महोदय, भगत सिंह कोश्यारी जी के बोलने के बाद मुझे समय ही नहीं मिला। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रकाश जावेडकर : आप अपना भाषण शुरू करिए, यह चलता रहेगा।

श्री वी. हनुमंत राव : अगले साल तक!

प्रकाश जावडेकर जी जो प्राइवेट मेम्बर बिल लाए हैं, उसके ऊपर सेपरेट तेलंगाना की बात सभी वक्ता लोग कर रहे हैं। स्पेशली मुझे ऐसा दिखा, बीजेपी और तेलुगु देशम। सबसे महत्वपूर्व बात यह है कि इन लोगों की एनडीए सरकार में **...(व्यवधान)...** मैंने आपकी बात तो सुनी, आप भी तो मेरी सुनिए, ज़रा सब्र कीजिए न। हम आपको पूरा सुनते रहे, आखिरी वक्त में हमें चांस दिया गया, उसमें भी बीच में अड़ंगा डालेंगे, तो हम कैसे बोलेंगे। मेरे बोलने का मतलब है कि जब उनका चांस था, इन्होंने दो स्टेट बोला। काकीनाडा सभा में बीजेपी की जो बैठक हुई, उस बैठक में इन्होंने कहा। उस वक्त मैं समझा था कि वेंकैया नायडु जी ईमानदारी से काम

5.00 P.M.

[श्री वी. हनुमंत राव]

करेंगे, क्योंकि 1972 में यही वेंकैया नायडु आन्ध्र ऐजिटेशन के लीडर थे। जब वे आन्ध्र यूनिवर्सिटी में लीडर थे, तो उन्होंने आन्ध्र मूवमेंट चलाया था। जब हमने 1969 में तेलंगाना का मूवमेंट चलाया था, उस वक्त वेंकैया नायडु जी ने भी आन्ध्र मूवमेंट चलाया था। उस वक्त उन्होंने काकरानी वेंकटरत्नम साहब के नेतृत्व में काम किया था। मैं समझा कि चलो, एक शुरुआत हो रही है। आज हमारे देवेंदर गौड साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वे ईमानदारी से तेलंगाना चाहते हैं, लेकिन उनका लीडर ऐसा नहीं चाह रहा। प्रॉब्लम वहाँ है, एन.टी रामाराव जी के समय चांस था। सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्दुस्तान में हर आदमी कह रहा है कि आन्ध्र प्रदेश डिवाइड हो रहा है। यह डिवाइड नहीं है, यह अटैच-डिटैच है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वह अलग है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, वह उसका पार्ट है, वैसे ही बिहार से झारखंड अलग हुआ, वह उसका पार्ट है, लेकिन हमारा तो पार्ट ही नहीं है। हमारा एक अलग स्टेट था, निजाम स्टेट। हमारा अपना रेलवे स्टेशन था, अपनी यूनिवर्सिटी थी, अपना हॉस्पिटल था, हम खुशहाल थे, मगर हम पढ़ाई में कमजोर थे, क्योंकि हमारी निजाम सरकार पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा पीछे थी। सिर्फ डायमंड, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाना, इनमें उनका ध्यान था, मगर इस वक्त आंध्र के लोग, जो मद्रास प्रोविंस में थे, वहाँ मिशनरी स्कूल्स बहुत थे, वहाँ मिशनरी की वजह से सभी लोग बहुत पढ़े-लिखे हो गए थे। उसके बाद जब 1954 में बुरुगुला रामकृष्ण राव यहाँ मुख्य मंत्री थे, उधर बैजवाडा गोपाल रेड्डी मुख्य मंत्री थे। जब पोट्टी श्रीरामुलु साहब ने ऐजिटेशन किया, तो मद्रास हमें दीजिए, ऐसा कह कर ऐजिटेशन किया। ऑरिजनली यह मद्रास एजिटेशन से स्टार्ट हुआ। उसके बाद तेलुगु भाषा के ऊपर ऐजिटेशन हुआ। अंत में आन्ध्र प्रदेश एक भाषा के नाम पर बना। उस वक्त हमने यह भी कहा कि देखिए, हम तेलंगाना वाले पढ़े-लिखे नहीं हैं, हम पिछड़ा वर्ग हैं, आप पढ़े-लिखे हैं, क्योंकि मद्रास में ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं, आप कॉलेजिज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ कर आए हैं, हमारे पास पढ़ाई कम है, आप लोग आकर हमारे ऊपर हावी होंगे। उसी वक्त हमने संजीवा रेड्डी साहब को बोला, मगर संजीवा रेड्डी साहब ने कहा कि नहीं, हम बराबर आपकी तरक्की करेंगे, आपके पास भी स्कूल्स खोलेंगे, आपके पास भी कॉलेजिज़ खोलेंगे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, मगर हम पढ़ने में थोड़ा कमजोर थे। आज हम उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। हमारी जो बैकवर्डनेस है, वाइस चेयरमैन साहब, वह इस वजह से है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्णा-गोदावरी हमारे पास से जाती है, लेकिन हमने एक डैम भी नहीं बनाया। देखिए, हमारी निजाम सरकार ने कैसी गलती की। वही आगे जाने के बाद सर आर्थर काटन साहब, जो उस वक्त ब्रिटिश राज में थे, उन्होंने कैनल्स बनाए। उसी वजह से आज वहाँ खुशहाली है। हमारे पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। हम आज भी बोल रहे हैं कि हम भाइबंदी के साथ अलग होना चाहते हैं, हम तुम्हें हटाना नहीं चाहते। कोश्यारी जी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, आन्ध्र प्रदेश क्या इनके बाप की जागीर है?

सर, मद्रास से यह अलग हुआ। आज भी मद्रास में आन्ध्र के लाखों लोग हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं हैं **...(व्यवधान)...**

माननीय सदस्य : लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं।

श्री वी. हनुमंत राव : हां, करोड़ों लोग हैं, कोई गिनती नहीं हैं। यह सिर्फ बताने की बात है और लोगों में एक तरह का भय फैलाने का काम ये कर रहे हैं। उसी का यह नतीजा है।

दूसरी बात, आप यह भी देखिए, हम इतने साल से **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Mr. Hanumantha Rao, the discussion has not been concluded. You may continue your speech on the next Private Members' Resolution day.

श्री वी. हनुमंत राव : सर, उस दिन फिर से मौका नहीं मिलता है। आप आखिर में छोड़ देते हैं, आज भी आज भी आप वैसा ही कर रहे हैं। वहां तेलंगाना में अन्याय हो रहा है और यहां सदन में भी अन्याय हो रहा है **...(व्यवधान)...**

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh) : Sir, he should be allowed to be the first speaker on that day. ...(*Interruptions*)...

SHRI V. HANUMANTHA RAO : Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : I told you that you may continue your speech on the next Private Members' Resolution day. You may continue then. The discussion has not been concluded.

The House is adjourned to meet at 11 a.m. on 7th May, 2012.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 7th May, 2012.